THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. At 4.30. Whatever you want. It is not my problem.

SHRI DIPEN GHOSH: In that case, do you suggest that the discussion on the Motion of Thanks will remain suspended for some time?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. It remains suspended in the night also when we adjourn the House. *(Interruptions)*

SHRI DIPEN GHOSH: It is not a question of night. During the currency of the session. *(Interruptions)* Madam, it is not a question of joke.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. It is not a joke. I am very serious.

SHRI DIPEN GHOSH: I want to know because I have a Special Mention.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you at 4.30. If you want it at 4.30. we will take it up at 4.30. Four-thirty *(Interruptions)*

अब एकदम शान्ति के साथ राम नरेश यादव जी को सुनने की कृपा करें।

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDEND'S ADDRESS

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाये :—

> "राष्ट्रपति ने 24 फरवरी, 1992 को ससद् की दोनों सभाओं की बैठक में कृपया जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए राज्य सभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का दिग्दर्शक होता है। सरकार की नीति क्या है, सरकार की दृष्टि क्या है, कहां सरकार जाना चाहती है, इसका सारा संक्षिप्त विवरण, संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखायी पड़ता है। जब दिखाई पड़ता है तो महोदया, इस अवसर पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह जनतंत्र है और जनतंत्र में ससद् ही सर्वोच्च संस्था है किसी देश की और आपके देश में जो लोक सभा और राज्य सभा है, यह सर्वोच्च सस्थाएं हैं। जनतंत्र में आपसी विचार-विमर्श के आधार पर, बहस के आधार पर निर्णय हुआ करते हैं और निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय देश की जनता के सामने जाता है। जो सरकार की मशीनरी है उसे कार्य रूप में परिणत करती है इसलिए ऐसे समय में इस अभिभाषण में जो राष्ट्र के सामने चुनौतियां खड़ी हैं चाहे आतकवाद की हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो या और जो सारी समस्याएं हैं गरीबी निवारण की समस्या है, उन सारी चुनौतियों का एक तरह से संकेत मात्र दिया गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पहली बार महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं उधर बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि जब जनतंत्र में सब को अपनी बात कहने का हक हासिल है, विचार-विमर्श करने का हक हासिल है तो उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण को बहुत शान्तिपूर्वक सुनना चाहिये था, उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिये था क्योंकि उससे बल मिलता है सुनने और उसके बाद चिंतन करने का भी। इधर कई दिनों से जिस तरह से सदन की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न किया जाता है किसी न किसी प्रश्न को लेकर के वह समय जो राष्ट्र की जनता का है जिसमें सारा पैसा लगता वह एक तरह से अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है उसकी तरफ से अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। उस तरफ से सारे सांसदों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आपके सामने चुनौतियां हैं और अवसर भी है (व्यवधान) चुनौतियां भी हैं और इस से बढ़िया सदन में कोई दूसरा अवसर भी नहीं मिलता है जहां विपक्ष अपनी भावनाओं को, सरकार की नीतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को रख सके अगर इससे बढ़िया अवसर होता तो मैं मोरारका जी से भी कहता चलिये हम लोग बैठ कर विचार करेंगे लेकिन इन चुनौतियों को सामने रखने के लिए सदन से उपयुक्त, इस सदन से उपयुक्त कोई दूसरी संस्था जनतंत्र में नहीं हो सकती है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने पहले ही कुछ

[श्री राम नरेश यादव]

समस्याओं की चर्चा की है जो राजनीतिक हैं और राजनीतिक चर्चा करते समय पंजाब की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित किया है। महोदय, पंजाब जो क्रान्तिकारियों की धरती रही, जहां पर जलियांवाला बाग गोली का हुआ, साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए लाला लाजपतराय पर लाठियां पड़ीं, ब्रिटिश सरकार के दमन का विचार वह धरती रही और ऐसी धरती जहां से गुरु नानक जी का शान्ति, अहिंसा और प्रेम का संदेश आया, गुरुग्रन्थ साहब का वर्तमान दर्शन जिस धरती पर हो, पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से उस धरती पर आतंकवाद की जड़ें जिस तरह से जम गई हैं वह देश के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उधर बैठे हुए लोग जब सत्ता में आए थे, आने की बात कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा था कि Elections to the Punjab Assembly will be held expeditiously.

हम पंजाब में चुनाव जल्दी करा देंगे। वह तो चले ही गये, इधर से उधर जा बैठे हैं लेकिन पंजाब का चुनाव नहीं करा सके तथा वहां पर जो आतंकवाद की स्थिति थी उसका सामना भी नहीं कर सके।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI S. JAIPAL REDDY): Madam, I would like to put the record straight. The election process was started in Punjab. The Congress(I) boycotted that election. And the Congress (I) which has come to power again got the election cancelled. You must first apologise to the nation. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please. Mr. Jaipal Reddy.

SHRI S. JAIPAL REDDY: You have not participated in the election.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, Mr. Jaipal Reddy. Let me remind the House that the meaning of a discussion from every section of the House is that while you get your chance, you can say if he has said anything wrong. If you keep on interrrupting, then I am sure, you are not going to agree with every word Mr. Ram Naresh Yadav says. So, let us not do that.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): On facts, we will challenge. If it is totally wrong, it has to be challenged.

SHRI S. JAIPAL REDDY: The fact of the history is that the election process started in Punjab, and you could not participate in the election. You got the election postponed. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please do not interrupt. I am not allowing any interruptions.

श्री ईश दत्त यादव : महोदया . . .

उपसभापति : आप डिप्टी लीडर हैं अपनी पार्टी के, बैठिए. (व्यवधान)

That is not proper. I am not allowing. Anybody who speaks without my permission is not going on record. (*Interruptions*)

बैठिए, बैठ जाइये।

I am not allowing anything.

SHRI YASHWANT SINHA: **

उपसभापति : राम नरेश जी बोलिए आप। कंटीन्यू करें। आप बोलते रहिए।

श्री राम नरेश यादव : महोदया, यह नेशनल फ्रंट का घोषणापत्र मेरे हाथ में है जो पूरे देश की जनता के सामने गया था और जिसके आधार पर इन लोगों ने चुनावी वादे किये थे। इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल फ्रंट जब सत्ता में आया तो इन्होंने (व्यवधान) आप भी इनके साथ में थे (व्यवधान) नेशनल फ्रंट साथ में था।

उपसभापति : आप जरा कृपया खामोशी से सुनिए (व्यवधान)

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Madam, he should also maintain discipline.

---

*Not recorded.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I tell you one thing. I am repeating it again. I don't believe you are going to agree with Mr. Ram Naresh Yadav. So, whatever he says, you are not going to believe it. So, let him speak. This is not the only point you are not agreeing to. And I am sure he is not going to agree to what you say. So, let us have a discussion in healthy spirit. *(Interruptions)* Please This is the meaning of democracy. Please have patience and tolerance. And I request the same from this side also. बोलिये।

श्री राम नरेश यादव : महोदया, चुनाव तो नहीं करा सके...

उपसभापति : अभी जरा चुप हो जाइये।

श्री राम नरेश यादव : चुनाव तो नहीं करा सके। इतना जरूर एक काम हुआ कि ये लोग आपस में टूटकर कोई इधर बैठे, कोई उधर बैठे। इतना जरूर हो गया। इसीलिए मामले को हल नहीं कर सके। जहां तक कांग्रेस पार्टी का ...(**व्यवधान**)

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Madam, they changed only positions but Mr. Yadav has changed parties.

श्री राम नरेश यादव : महोदया, वास्तविकता यह है कि पंजाब की सीमा करीब 554 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान से और उस सीमा पर सरकार की तरफ से पिछले दिनों जो कदम उठाये गये थे हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी के नेतृत्व में जो कदम उठाये थे और इधर वर्तमान श्री पी०वी० नरसिंह राव के कुशल नेतृत्व जो कदम उठाये गये हैं उनके आधार पर एक बात तो साफ दिखाई पड़ती है कि उस आतंकवाद को रोकने के लिए—क्योंकि बाहर से लोग आते थे, आतंकवादी आते थे, जो हथियार लेकर आते थे, जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आते थे पंजाब में उनके जरिये जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था उसको रोकने के लिए बाड़ लगायी गयी और उसके साथ साथ फ्लड लाइट का इंतजाम किया गया करीब 384 किलोमीटर तक। इन सब चीजों के साथ साथ एक चीज थी जो विशेष रूप से बहुत चिंता का विषय बनी हुई थी जिसकी तरफ पिछली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण जब सदनों में हुआ था तो उस समय भी, 21 फरवरी, को उन्होंने पूरे देश की जनता का ध्यान उधर दिलाया था। सचमुच एक चिंता का विषय बन गया था इसलिए कि 1990-91 में 5058 लोग मारे गये थे, उस आतंकवाद के शिकार हुए थे और 1978-79 तक कुल 5070 लोग मौत के शिकार हुए थे, उनकी हत्यायें हुई थीं। इसलिए एक साल के अंदर इतने लोगों की हत्या का होना पूरे देश के लिए एक चिंता का माहौल बनना, वातावरण बनना बहुत ही आवश्यक था, इस बात को ध्यान में रखकर ही पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद पंजाब की समस्या को हल करने के लिए—एक बात तो जरूर दिखाई पड़ती है कि जनता के हाथों में पंजाब के शासन को सौंप दें। चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में, जनता के हाथों में पंजाब के भाग्य का फैसला करने का अधिकार उन्हें देने का काम किया है। यह निर्णय घोषणा-पत्र में किया गया था और उसके आधार पर चुनाव भी हुआ, चुनाव के नतीजे भी आए और, महोदया, बहुत प्रसन्नता की बात है कि बेअंत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, जो निश्चित रूप से जो वहां की चुनौतियां हैं, पंजाब के सामने जो आतंकवाद बढ़ा हुआ है, उन सारी समस्याओं को हल करने में गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि चुनाव के नतीजे जो आए, उसमें भी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब जनतांत्रिक ढंग से चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेकर उस पंजाब की समस्या को हल करने का समय आ रहा था, उस समय भी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और बहिष्कार करके जो एक जनतांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है—आप चुनाव में भाग लेते।

कांग्रेस पार्टी ने अगर उस समय रद्द कर दिया था, चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया था, उस बात को जनता के

[श्री राम नरेश यादव]

बीच में लेकर आप जाते और कहते कि कांग्रेस की सरकार ने गलत काम किया है। उसका फायदा आपको मिलता या कांग्रेस को मिलता। यह बात चुनाव के बाद मतदान के बाद आ जाती, लेकिन आपने वह भी, कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं की, चुनाव का बहिष्कार किया। लेकिन इसके बावजूद भी वहां की जनता ने, उस आतंकवाद की परिस्थिति में जहां पर कि हिंसा का माहौल हो, जहां पर कि घोर आतंकवाद का वातावरण व्याप्त हो, उस परिस्थिति में भी कितनी दिलेरी और साहस से काम लेकर जनतांत्रिक तरीके में विश्वास करके जिस तरह से मतदान केन्द्रों पर जाकर मतदान किया और कांग्रेस के पक्ष में विधान सभा में भी दो-तिहाई से अधिक बहुमत प्राप्त करके कांग्रेस पार्टी ने वहां पर एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है और जनता के हाथों में, जो चुने हुए लोग थे, उनके हाथों में शासन की बागडोर देकर पंजाब की समस्या को हल करने का एक अवसर दिया है।

इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि चुनौती भी है और अवसर भी है और उस अवसर का लाभ वहां की सरकार लोगों से बात करके--एक बात बहुत साफ है कि संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने कई एक अवसरों पर कहा है और कल भी कहा है कि हम संवैधानिक ढांचे के अंदर रह कर इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किसी भी शक्ति से चाहे वह सिख स्टुडेंट फेडरेशन हो चाहे और भी जो वहां के आतंकवादी संगठन हैं उनसे मिल करके भी बातचीत करने के लिए भी सरकार पीछे नहीं रहेगी। इसलिए यह भी मामला अपनी जगह पर बहुत ही स्पष्ट है।

साथ ही कश्मीर का मामला भी वैसा ही है। महोदया कश्मीर में सीमा के पार से दलों का आना वैसी ही स्थिति है आतंकवादियों की सहायता, हथियार देना और उसमें विशेष रूप से एक बात साफ है कि पाकिस्तान में जो तथाकथित समायोजन पाक आक्युपाइड कश्मीर की बात कही जाती है वहां पचासों शिक्षण के केन्द्र भी है। वहां से हथियार भी आते हैं लोग लेकर घुसते हैं और घुसने के बाद कश्मीर की उस धरती को जो धरती का स्वर्ग माना जाता है, परियों का देश माना जाता है, ऐसे कश्मीर को जहां के झरने, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य और ऐसा कश्मीर, जिस कश्मीर में इस देश के अंदर जो हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म की व्याख्या की गई, है, व्यवस्था की गई है, उस कश्मीर ने सेक्युलरिज्म का जिस तरह से परिचय दिया था, वह कश्मीर आज जिस तरह से एक ऐसा अड्डा बन गया है, वह भी एक चुनौती है पूरे देश के लिए राष्ट्र के लिए और चिंता का विषय भी है।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस तरह सारे अपहरण की घटनायें हो रही हैं और 56 हजार परिवार कश्मीर को छोड कर जिस तरह से वहां से भागे हैं, दूसरी जगहों पर शरण ले रहे हैं, उनकी भी समस्या का समाधान करने का सवाल है।

इन सारी चीजों के होते हुए जबकि पाकिस्तान का हाथ दिखाई पड़ता है, अभी पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बात भी की। प्रधान मंत्री भी आये थे, उनसे भी सारी बातें हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से वहां के जो कई संगठन हैं और उनके आधार पर जो वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है, यह बहुत ही गंभीर विषय है। उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान गया है।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सचमुच में इधर पिछले दिनों जिस तरह से अमानउल्ला खां ने जो कश्मीर में घुसने की धमकी दी थी, सरकार की जो तैयारी थी, उसके आधार पर जो लाईन आफ एक्चुअल कंट्रोल है, सरहद, है, जो नियंत्रण रेखा है, उसको वह पार नहीं कर सके। अब फिर उन्होंने चुनौती दी है कि 30 मार्च को वह अपने सारे दल बल के साथ प्रवेश करेंगे। यह मामला भी एक गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। वह भारत से अलग नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? इसलिए कि हमारे सामने कहीं-कहीं पर ऐसे अवसर भी आते हैं जब कुछ लोग शेख अब्दुल्ला के चरित्र पर भी और उनकी राष्ट्रीयता पर भी, उनका

जो सैकुलर चरित्र है उस पर भी आरोप और आक्षेप लगाने की बात कहते हैं। लेकिन इस सदन को धन्यवाद देना चाहिए, आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि शेख अब्दुल्ला ने जिस तरह से उस परिस्थिति में जबकि दो राष्ट्र का सिद्धांत पाकिस्तान मांग रहा था मो0 अली जिन्नाह ने पूरे देश के सामने दिया था अगर शेख अब्दुल्ला चाहते, वहां की जो सैकुलर फोर्सेज नहीं थीं वह अगर चाहतीं तो वह पाकिस्तान के साथ भी जा सकती थीं, लेकिन ऐसे समय में सन् 1947 में जबकि कबायली लोगों ने आक्रमण किया वहां पर कितना नुकसान किया, कितना उजाड़ने का काम किया ये सारी चीजें जब होती रहीं हथियारों से लैस हो कर लोग आते रहे उस समय भी उस परिस्थिति में शेख अब्दुल्ला ने वहां की रियासत ने जिस तरह से एक एतिहासिक परिचय देने का काम किया राष्ट्रीयता का परिचय दिया वह भी अपने आप में एक बेमिसाल है। क्योंकि अगर नहीं चाहते तो काश्मीर भारत का अंग नहीं बनता। जो सन् 1947 का विलय हुआ एक्शन हुआ, वह सच मुच में आज भी हिन्दुस्तान के लिए एक ऐसी चीज है कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बन चुका है। किसी भी कीमत पर वह हम से अलग नहीं हो सकता और भारत का एक-एक नागरिक किसी भी कीमत पर जो लोग कि वहां पर सांप्रायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं उन्हें भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होगा।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : जगमोहन साहब जी का स्टेटमेंट . . . (व्यवधान)

उपसभापति : अभी बैठिए। (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : मेरे साथी बी.जे.पी. के लोगों का उतावला होना कुछ स्वाभाविक है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जोशी जी ने जम्मू को काश्मीर से भी अलग करने की बात कह दी। एक तरफ तो काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग और दूसरी तरफ जम्मू और काश्मीर को भी अलग से राज्य बनाने की मांग अभी थोड़े ही दिन पहले किया है। साथ ही साथ महोदया यह लोग तो क्या से क्या नहीं कर डाले हैं आज जो इस समय, अभी फिर यह जो अब्दुल क्यूम साहब ने, जो कि कथित काश्मीर के सो-काल्ड प्रधान मंत्री कहे जाते हैं सरकार क्यूम, जिन्होंने कहा है कि हम खुद नियंत्रण रेखा को पार करेंगे और अभी अमानुल्ला ने भी कहा जो कि जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम 30 तारीख को नियन्त्रण रेखा को पार करेंगे। मैं तो यह कह रहा हूं कि आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है, कौन जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार हैं वह लोग जिन लोगों ने एकता के नाम पर एकता यात्रा करके काश्मीर के उन दिलों को भी तोड़ने का काम किया, पिछले दिनों जो कि हमारी सरकार ने कदम उठाया था मिलिट्री भेज करके वहां पर चुनाव कराने का माहौल बनाने की जो प्रक्रिया थी उसे तेज करने की दिशा में कदम उठाया था, उस पर भी आघात पहुंचाने का काम किया है, बल्कि सारे जितने आतंकवादी थे उन आतंकवादियों को ला करके एक कर दिया है। परिणाम यह हुआ कि चारों ओर से वह सारे लोग हत्या करने में और अपहरण करने में लग गए हैं। जब शेख अब्दुल्ला की बात आती है, महोदया, अगर कहीं इस समय का बयान होता तो बात कुछ दूसरी होती, लेकिन मैं सैक्यूरिटी कौंसिल में . . . (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : आप मानते हैं कि सन् 1953 में जब जवाहरलाल नेहरू ने गिरफ्तार करके . . . (व्यवधान)

उपसभापति : आपका नाम जबग्राए गा मैं आपको जरूर बुलाउंगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह तो जानकारी (व्यवधान)

उपसभापति : जानकारी जो भी होगी वह दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वह जबाव दें।

उपसभापति : वह जवाब दे या नहीं दें मगर मैं एलाउ नहीं कर रहीं हूं... (व्यवधान) बोलने दीजिए।

He is the Mover. Let us not disturb his trend of thought.

श्री राम नरेश यादव : महोदया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे विपक्ष के लोग वास्तविकता को भी स्वीकार नहीं करते और वह स्वीकार करने का मतलब कि काश्मीर का भारत के साथ विलय होना और उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा कौंसिल में जब शेख अब्दुल ने जो बयान दिया था और उसके बाहर भी जिस तरह के बयान हमने दिए थे वह इस बात का सबूत है कि सचमुच में किस तरह से उनमें राष्ट्रीयता का भाव सेक्युलरिज्म का भाव था, लोगों को लेकर चलने का भाव था जबकि कोई दबाव भी उनके ऊपर नहीं था। उन्होंने सेक्युरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी, पेज-21 पर कहा है कि–

"I was explaining how the dispute arise—how Pakistan wanted to force this position of slavery upon us. Pakistan had no interest in our liberation—let me repeat—Pakistan had no interest in our freedom movement. Pakistan would have supported us when thousands of my countrymen were behind bars and hundreds were shot to death."

उसके आगे फिर 24वें पेज पर कहा है–

"The Pakistani leaders and Pakistani papers were heaping abuse upon the people of Kashmir who were suffering these tortures."

फिर उन्होंने कहा है –

"Then, suddenly, Pakistan comes before the bar of the world as the champion of the liberty of the people of Jammu and Kashmir."

इस तरह कहने के बाद फिर उन्होंने कहा है–

"I had thought all along that...

फिर कहा है–

"When the raiders came to our land, massacred thousands of people—mostly Hindus and Sikhs, but Muslims too—abducted thousands of girls, Hindus, Sikhs and Muslims alike, looted our property and almost reached the gates of our summer capital, Srinagar, the result was that the civil, military and police administration failed."

आगे कहा है–

"These raiders abducted women... Under these circumstances, both the Maharaja and the people of Kashmir requested the Government of India to accept our accession."

उन्होंने कहा कि सरकार ने एक्सेसन कर लिया, इसलिए अब आज उस बात को ध्यान में रखकर जो विशेष परिस्थिति एक्सेसन के समय थी, आर्टिकल–370 की जो व्यवस्था की गयी थी, उसको हटाने की बात जो बी.जे.पी. के लोग कहते हैं और कुछ दूसरे साथी कहते हैं, वह सचमुच में जो काश्मीर की स्थिति ठीक बनती है, रह-रहकर ये उसके घावों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। उस विशेष परिस्थिति को हटाकर वहां के लोगों में एक अविश्वास की भावना भारत के प्रति पैदा करना चाहते हैं। महोदया, सरकार ने कहा है और प्रधान मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार से आर्टिकल–370 को हम नहीं हटा सकते जोकि विशेष परिस्थितियों में उस समय संविधान की मान्यता के आधार पर उनको दी गयी थी।

साथ-ही-साथ महोदया कुछ कदम भी उठाए गए हैं–बाढ़ लगायी गयी है, सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है, बातचीत की भी सरकार इच्छुक है और अभी पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने भी आतंकवाद से निपटने के लिए, जम्मू-काश्मीर और पंजाब की समस्या पर विचार करने के लिए सारे विरोधी दलों के नेताओं की बैठक बुलायी थी। आखिर और क्या रास्ता हो सकता है ? इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि जनतंत्र में आपसी विचार-विमर्श

आपसी बातचीत और आम सहमति के आधार पर ही तो निर्णय लिए जा सकते हैं। कहीं से कोई बाहरी निर्णय तो नहीं लादा जा सकता है और न थोपा जा सकता है ?

महोदया, जो इन्होंने एकता यात्रा की थी, उससे सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि पूरे प्रदेशों में जहां-जहां से भी एकता यात्रा गुजरी वहां स्थिति खराब हुई। अयोध्या में, लखनऊ में, और हापुड़ में और इससे पहले भी कुछ और स्थानों में हो गई। यह सारी चीजें इसलिए हुईं कि जिस-जिस रास्ते से लोग गए वहां पर जिस तरह से इनके भाषण होते थे, उससे भी यह हुआ क्योंकि झांसी में सारी सरकार जाकर स्वागत करती है और आगरा में विदाई देती है। लखनऊ में जाकर बाहर स्वागत करती है। आखिर यह क्या हो रहा है ?

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदय, हमारी आलोचना के बगैर तो इनका हाजमा भी ठीक नहीं रहता है। इसलिए इन्हें हाजमोला की गोलियों की एक-एक शीशी दे दी जाय।

श्री राम नरेश यादव : महोदया, एक तरफ तो ये लोग संविधान की शपथ खाते हैं और शपथ खाने के बाद अपना ऐसा चरित्र प्रदर्शित करते हैं कि जिस चरित्र के आधार पर सचमुच में देश के अंदर एक सांप्रदायिकता की आग जलती है, लोगों के दिल टूटते हैं और आपस में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना जागती है। लेकिन यह देश तो जिस सेकुलरिज्म के आधार पर चला था, स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी वही हमारा आदर्श रहा कि, "सर्वधर्म समभाव" और आज भी कांग्रेस का जो आधार और दर्शन है, उसी आधार पर कांग्रेस चलती रही है। इन बातों को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति जी ने कदम उठाने की बात कही है। आखिर दूसरे और कौन से रास्ते हो सकते हैं जिससे जनतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाय। बातचीत है, अभी हुई है और फिर इसके बाद अभी फिर बात की गई है कि कैसे लोकल बोडोज के चुनाव कराये जायें। अभी गृहमंत्री जी ने भी कहा था, पिछले दिनों घोषणा थी कि हम चाहते हैं कि हमारी जो सेना है वह सेना जिस तरह से माहौल पैदा कर रही है, उस आधार पर कोई भी कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा तो उठाए जायेंगे, लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी ताकि जिस तरह से अभी पंजाब में जनतंत्र बहाल हुआ है उसी तरह कश्मीर में भी आने वाले दिनों में वह वातावरण बने ताकि वहां के लोग उसी तरह से चुनाव में जनतांत्रिक आधार पर भाग लेकर अपने भाग्य का निपटारा करने में सक्षम और समर्थ हो सकें। यही आज की आवश्यकता है।

मैडम, उसी तरह से इधर हमारे पूर्वोत्तर में आसाम, आसाम में अलफा, उधर भी राष्ट्रपति जी ने ध्यान आकर्षित किया है। वह भी एक चिंता का विषय है क्योंकि अभी सितंबर, 1991 में वहां पर फौज भी भेजी गई। पिछले दिनों चुनाव भी हुआ, अपनी सरकार है, सरकार चल भी रही है, लेकिन अलफा के लोगों ने भी, जो पिछले दिनों आंदोलन कर रहे थे, उनमें बहुत से लोगों ने सरेण्डर भी किया, गिरफ्तारियां भी हुईं। इधर बोडो के लोग भी कुछ अपना आंदोलन चलाना चाहते थे। कई तरह के लोग थे, जिन्होंने अपने-अपने ढंग से आसाम में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। आज वहां श्री हितेश्वर सैकिया की कांग्रेस सरकार है, वह लगी हुई है उनसे बातचीत करने में और बातचीत के आधार पर अभी पिछले दिनों फिर से, वहां पर मिलटरी ने जो अपना सारा अभियान छेड़ रखा था; वह कुछ स्थगित कर दिया था और वह इसलिए कि वातावरण बने कुछ बातचीत का और बातचीत के वातावरण के सिलसिले में यह बात भी साफ है, पहले ही मैंने कह दिया कि जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, जो हमारा संविधान है, जिसमें अपने देश की, स्वायत्तता की रक्षा करने का सवाल है उस सवाल को ध्यान में रखकर उन लोगों के सामने घुटने टेकने का सवाल नहीं है बल्कि उस दायरे में किसी तरह से भी कोई बात करने में सरकार न तो हिचकिचाएगी और न दूसरे लोग हिचकिचायेंगे। इसलिए इस आधार पर सरकार का ध्यान, राष्ट्रपति महोदय का ध्यान गया है। यह

(श्री संघ प्रिय गौतम)

आज एक चुनौती है क्योंकि यह आतंकवाद राष्ट्रीय समस्या है, एक दल की समस्या नहीं है और जब एक दल की समस्या नहीं है बल्कि राष्ट्रीय समस्या बन गई तो इधर के बैठे हुए लोग हों चाहे विपक्ष के लोग सारे हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि मिलजुलकर एक कानसेन्सस के आधार पर समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि जनतांत्रिक ढंग से वहां पर भी, कश्मीर में जैसी स्थिति बनने वाली है, आसाम में जो बनी है, इसका निवारण हो सके क्योंकि हमारा तेल उत्पाद, कच्चा माल पेट्रोलियम पदार्थ पैदा होता है, उसमें जिस तरह से रह-रह कर सारी स्थिति पैदा हो जाती है वह न हो क्योंकि यह भी हमारे विकास में बाधा बनती है इसलिए उधर भी सरकार का ध्यान गया है और यह एक अच्छी चीज हुई है ।

महोदया, दूसरी बात यह है कि सचमुच में यह जो रामजन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद की जो स्थिति है, इस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस आधार पर कहा है कि रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से उत्पन्न स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है यह सचमुच में हमारी जो राष्ट्रीयता है, हमारी जो एकता है और हमारा जो धर्म-निरपेक्ष दर्शन है देश का, सरकार का उस पर भी कभी-कभी घातक प्रहार होते हैं और जब घातक प्रहार हो जाते हैं, कुछ संकुचित मनोवृत्ति के द्वारा, कुछ सोच के द्वारा जाने या अनजाने कहीं पर तो उससे देश के लोगों को और ऐसे लोगों को, जो देश को एक सूत्र में पिरोकर, बांधकर ले चलना चाहते हैं उनको बड़ी चोट पहुंचती है । इसी बात को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय एकीकरण की बैठक भी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी और उसमें इन सारे प्रश्नों पर विचार भी हुआ था । एक बात जो बहुत जरूरी है, इस सिलसिले में कट्टरवादिता जो है, वह जो धार्मिक लोग हैं उनकी कट्टरवादिता में अंतर्द्वन्द होता है । उसके बीच से ही सांप्रदायिकता का जन्म होता है और जब सांप्रदायिकता का जन्म होता है तो उसके परिणाम बड़े घातक और बुरे होते हैं क्योंकि यही स्थिति वहां देखने को मिली है । पिछले 105 वर्षों से कांग्रेस हमारी हजारों साल पुरानी स्वर्णिम सभ्यता में व्याप्त अनेकता में एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती रही है, इसे अपनी मान्यताओं का आधार बनाती रही है । धर्मनिरपेक्षता के हमारे दर्शन का यह मूल आधार है । सर्वधर्म समभाव की हमारी इस महान सांस्कृतिक विरासत पर कभी-कभी घातक हमला हो जाता है और ऐसे पृथकतावादी, जिनकी साम्प्रदायिक सोच है, उनको हम भारतीय मानस के टुकड़े करने नहीं दे सकते । हम भारत के लोगों की भावनात्मक एकता को नष्ट नहीं होने दे सकते और अपने एक समाज को खंडित नहीं होने दे सकते ।

1951 में इसी प्रश्न पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि "यदि कोई मनुष्य धर्म के नाम पर किसी दूसरे मनुष्य पर हाथ उठाता है तो उसके खिलाफ मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, चाहे मैं सरकार में रहूं या उसके बाहर।" यह हमारे सैक्यूलरिज्म का, उस दर्शन का आधार रहा है और जब यह आधार रहा है तो उसी आधार पर हमारी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में पहले ही कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद ये जो हमारे धार्मिक स्थल, पूजागृह हैं और इन पूजागृहों को लेकर के समय-समय पर जो देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाता है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, हम उसको नहीं तोड़ने देंगे । इसीलिए राजीव गांधी जी ने, जो उनका आखिरी दस्तावेज था, उस घोषणा-पत्र में इस बात की व्यवस्था की थी कि सत्ता में आने के बाद हम एक ऐसा विधेयक लाएंगे जिसके आधार पर कि 15 अगस्त, 1947 को जो स्थिति सभी धार्मिक पूजा-स्थलों की थी, उन स्थलों को उसी आधार पर हम रखेंगे ताकि आने वाले दिनों में कोई विवाद इस तरह का न हो सके, उसे दंडनीय अपराध भी माना जाएगा । पिछले दिनों सरकार ने एक बिल भी लाने का काम किया, वह विधेयक भी पास हो चुका है, कानून बन चुका है और

उसके पीछे मंशा यह थी कि आखिर धर्म की आड़ में जिस तरह से नाटक और खेल खेला जाता है और आज भी राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के नाम पर जिस तरह से, रह रह कर यह चीज में नहीं कहना चाहता, लम्बी कहानी हो जाएगी, मगर इतना जरूर है कि उधर बैठे हुए लोगों ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया था, पूरे देश के अंदर जो एक आग लगी थी उससे जो लोग तबाह और परेशान हुए थे, यह सब लोगों के सामने है और उनको भी ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाया गया है और साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित परिवारों की देखभाल करने के लिए भी साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान बनाया गया है ।

मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत दिनों से जो एक मांग चली आ रही थी कि जब साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, लोगों के खून गिरते हैं, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उस समय तो साम्प्रदायिकता में मनुष्य मदान्ध हो जाता है, समझ नहीं पाता है, इसलिए इन्सान का खून तो खून है और इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर बराबर यह मांग की जाती रही है कि जब ऐसे अवसरों पर कहीं पर पी.ए.सी. जाती है तो जाकर के वह भी पक्षपात करती है, इस तरह की मांग बहुत दिनों से उठाई जाती रही है । हमने घोषणा-पत्र में भी कहा था कि रेपिड एक्शन फोर्स, वह रेपिड एक्शन फोर्स, जैसा कि अभिभाषण से स्पष्ट होता है कि उसका गठन भी कर लिया गया है और यह गठन उस इतिहास की देन है जिसके आधार पर कोई भेदभाव न रहे देश में । ऐसे समय में एकरूपता रहे, समानता का व्यवहार रहे, भाईचारे का व्यवहार रहे और जो शासन की कड़ी है, वह कड़ी भी ऐसे मौके पर वैसा ही आचरण करे, इस बात को ध्यान में रखकर रेपिड एक्शन फोर्स का भी गठन हो गया है और उस रेपिड एक्शन फोर्स के गठन के पश्चात और भी जो कमियां होंगी, जो आप लोगों की तरफ से, उधर से जो कुछ सुझाव आएंगे, उनके संबंध में भी सरकार कुछ विचार करेगी क्योंकि यह देश तो सबका है । 85 करोड़ लोगों का यह देश है हिन्दू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सभी धार्मिक सम्प्रदायों के मानने वाले लोग यहां रहते हैं और अगर कहीं किसी धर्म के मानने वाले की भावना को ठेस पहुंचाकर के, कहीं मस्जिद को गिराकर के, मस्जिद को ठेस पहुंचाकर के कोई मंदिर बनाने की बात करता है, कहीं गुरुद्वारे को ठेस पहुंचाकर के कोई अगर मस्जिद बनाना चाहता है तो इस तरह की बात को अब इस देश के लोग पसंद नहीं करेंगे । इसलिए पसंद नहीं करेंगे कि सचमुच में देश का जो दर्शन है साम्प्रदायिक सौहार्द रखने का, लोगों को लेकर के चलने का, एक सूत्र में बांधकर के ले चलने का, उस पर किसी भी कीमत पर आघात नहीं आने देंगे और यही देश की सबसे बड़ी विजय है जिस आधार पर कि लोगों को चलना है ।

संविधान में जो व्यवस्था की गयी है उस व्यवस्था के आधार पर इसे लागू करके यह बता भी देना है कि हम किसी भी तरह से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकेंगे । बी.जे.पी. के लोग जरूर समय-समय पर कुछ कहा करते हैं । लेकिन अब उन लोगों को भी अपने को टटोलना पडेगा, देखना पड़ेगा और अंतर्मुखी होकर विचार करने के बाद ऐसे कदमों से, ऐसे रास्तों पर चलने से अपने को तैयार करना पड़ेगा । साम्प्रदायिक हिंसा से परिवार तबाह होता है, लोग मारे जाते हैं, बहुत नुकसान होता है । इसलिये साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुये परिवारों के बच्चों की देखभाल के लिये साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान की भी स्थापना की गई है ।

महोदया, बहुत दिनों से दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग चली आ रही थी । ... (**व्यवधान**) ...

श्री यशवन्त सिन्हा : एक घंटा और इनको दिया जाना चाहिये । .. (**व्यवधान**) ..

श्री राम नरेश यादव : आप लोग तो हमारे मित्र ही हैं... (**व्यवधान**) ...महोदया, दिल्ली के बारे में बहुत दिनों से जो विधान सभा की मांग चली आ रही थी उसकी भी हमारी सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की है और डि-लिमिटेशन की भी कार्रवाई हो रही

(श्री राम नरेश यादव)

है । यह एक ऐसा मामला है जिसकी तरफ भी पूर्ण ध्यान दिया गया है। . . (**व्यवधान**) :

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : राम नरेश यादव, जी, यह सब चीजें तो उसमें हैं, पढ़ लीजिये ।

श्री राम नरेश यादव : हां, इसीलिये मैं कह रहा हूं आपसे। आप समझिये कि सचमुच में जिस तरह से कदम उठाया गया है। यह आपके लिये है, क्योंकि आप लोग तो वाक आउट करके चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री एन०के० पी० साल्वे : (महाराष्ट्र) : आप सुनिये और समझिये।

श्री यशवन्त सिन्हा : आपके ऊधर जाने के बाद कोई तरक्की हो रही है ?

श्री राम नरेश यादव : हां, तरक्की हो रही है । तरक्की हो रही है, इसीलिये तो आप लोग भाग जाते हैं । आप तरक्की को नहीं देखना चाहते हैं। . . (**व्यवधान**)

श्री एन०के०पी० साल्वे : तरक्की नहीं, सुधार हुआ है।

श्री राम नरेश यादव : महोदया, देश की आर्थिक स्थिति की तरफ भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने सारा ध्यान खींचा है । मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो लोग उधर बैठे हुये हैं और आज जो बहुत हंस भी रहे हैं, इन लोगों को भी . . . (**व्यवधान**) . .

श्री ईश दत्त यादव : महोदया, हमारा, एक निवेदन है ।

उपसभापति : यह पोइंट आफ आर्डर है या निवेदन है ?

श्री ईश दत्त यादव : पोइंट आफ आर्डर है। (**व्यवधान**)

उपसभापति : पोइंट आफ निवेदन ।

श्री ईश दत्त यादव : महोदया, मेरा निवेदन है कि माननीय यादव जी, अपने सारे भाषण में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है, क्या करेगी, इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं (**व्यवधान**) केवल सारी आलोचना इधर की ही कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि . . . (**व्यवधान**)

श्री एन०के०पी० साल्वे : आपकी सरकार के बारे में जो कह रहे हैं, उसमें सब कुछ कह दिया है ।

श्री ईश दत्त यादव : आपकी सरकार की उपलब्धियां क्या है ? उत्तर प्रदेश जल रहा है, चार-चार, पांच-पांच . . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : उनकी जो मरजी है, वह बोलेंगे । आपकी मरजी से थोड़ी बोलेंगे ।

श्री प्रमोद महाजन : (महाराष्ट्र) : एक उपलब्धि तो राम नरेश यादव जी स्वयं हैं, जो. . . (**व्यवधान**)

श्री ईश दत्त यादव : आपकी सरकार ने आज तक क्या किया, आप तो उसको बताइये । आप उधर की कुछ बात नहीं बता रहे हैं, आप इधर की बात बोल रहे हैं ।

उपसभापति : इसमें कोई निवेदन नहीं है, बैठिये । देखिये, राम नरेश जी, जिस बात का प्रैजीडेंट को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वह बोल रहे हैं जो उनकी मरजी है । आप जो बोलना चाहे, आप बोलियेगा । उनकी मरजी है, वह जो चाहें, कहे ।

श्री यशवन्त सिन्हा : हम सब चाहते हैं कि वे लोग शुक्रिया अदा करें : (**व्यवधान**)

उपसभापति : दो मिनट और हैं । (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव : महोदया, पिछली सरकारों ने देश की आर्थिक स्थिति को इतना जर्जर कर दिया था, मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बहुत ज्यादा करके

सत्ता में आयी थी कि देश की स्थिति खराब है, हम इसे ठीक करेंगे, हम इसे पटरी पर लाने का काम करेंगे। इनके सत्ता में आने के बाद देश की आर्थिक स्थिति जो 15 महीने में बिगड़ी और खराब हुई, वह तो बहुत ही चिंता का विषय रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी जो नयी सरकार आई है, इस सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उन कदमों के परिणाम-स्वरूप ऐसी उपलब्धियां हुई हैं, जिनको ध्यान में रखकर आप लोग बाहर निकल जाते हैं, ताकि लोगों को सुनने का मौका ही नहीं मिले और इसलिए... **(व्यवधान)**

श्री यशवन्त सिन्हा : हम लोग बहुत तेजी से समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Still there is one more minute. Let him have his one minute.

श्री राम नरेश यादव : महोदया, सारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर करदी थी, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी साख इतनी गिरादी गई थी कि कोई देश आपको कर्ज भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऐसी भीषण आर्थिक स्थिति आपने पूरे मुल्क के पैमाने पर पैदा करदी थी। कोई देश आपको कर्ज तक देने के लिए तैयार नही हो रहा था, ऐसी भीषण आर्थिक स्थिति आपने पूरे मुल्क के पैमाने पर पैदा कर दी थी और तब ऐसी स्थिति में, सिन्हा जी यहां मौजूद हैं, वे तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वे हमारे मित्र भी हैं और उधर के सभी लोग हमारे मित्र हैं। मैं यह कह रहा था कि जहां करीब 5600 करोड़ रुपए का रिजर्व राजीव गांधी की सरकार ने छोड़ा था, ये लोग जो व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे, कहते थे कि देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना चाहते हैं, इन लोगों ने पटरी पर लाते-लाते जो फारेन एक्सचेंज रिजर्व था, उसे इतना गिरा दिया कि एक्सीडेंट हो गया और 2100 करोड़ रुपए का फरेन एक्सचेंज रह गया। देश के लिए इससे बढ़कर चिंता की बात और क्या हो सकती है? महोदया, देश को गिरवी रखने की बात भी कही गई... **(व्यवधान)**

उपसभापति : राम नरेश जी, अब लंच का समय हो गया है। लंच आवर के बाद अगर आप बोलना चाहें तो जरूर बोलियगा।

The House is adjourned till 2.30 p.m. for lunch.

The House then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Bashkar Annaji Masodkar)** in the Chair.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS— Contd.

श्री राम नरेश यादव : मैं यह कह रहा था कि देश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई थी और उस जर्जर स्थिति से निकालने की जिम्मेदारी नई सरकार के ऊपर आई। उस समय प्रश्न यह था कि कैसे भुगतान संतुलन की स्थिति को ठीक किया जाए, कैसे जो विदेशी मुद्रा रक्षित भंडार में कम हो गई है उसको सुधारा जाए। साथ-साथ कैसे उद्योग बढ़ाये जायें, आर्थिक स्थिति को ठीक करके विकास की गाड़ी को तेज किया जाए ये तीन प्रश्न देश के सामने थे और ये प्रश्न इसलिए सामने थे कि जो एन०आर०आई० है उनकी ऐसी स्थिति बन गई थी कि करीब-करीब 300 करोड़ रुपया प्रति सप्ताह यहां से बाहर ले जा रहे थे। बाहर से एन.आर.आई. की पूंजी आने के बजाए यहां से पूंजी को बाहर ले जाने का क्रम शुरू हो गया था जिससे काफी नुकसान था। इसी कारण विदेशी मुद्रा रक्षित भंडार में कमी हो गई थी। इसके साथ-साथ कोई दूसरा देश देने को तैयार नहीं था। इसीलिए सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत थी।

पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मंगाने थे। इस समय देश में फर्टीलाइजर का कुल उत्पादन एक करोड़ टन हो रहा है जबकि खपत 125 लाख टन है बल्कि इससे ऊपर ही है। इसलिए जरूरी है कि कृषि की तरफ ध्यान देना है, उत्पादन बढ़ाना है। इस बात को ध्यान में रख कर फर्टीलाइजर

(श्री राम नरेश यादव)

और दूसरे पदार्थों का आयात करना बहुत ही आवश्यक है। खाने के तेल की कमी है इसलिए उसे भी आयात करना जरूरी था, उद्योग के लिए कच्चा माल आता है, सूत आता है, दूसरी चीजें आती हैं जिसके आधार पर यहां इंडस्ट्री चले, कोई इंडस्ट्री पर दिक्कत न पहुंचे, उद्योग पर दिक्कत न पहुंचे। क्योंकि उद्योग में हमारे लोग लगे हुए हैं जबतक उद्योग का विकास नहीं होगा उनका स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। हमारे देश के उद्योग में कृषि को भी मिलाकर जो हमारे यहां की शक्ति है उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तीन प्रश्न गम्भीर हमारे सामने थे। इसलिए कुछ कड़े कदम उठाना सरकार के लिए जरूरी था और सरकार ने कदम उठाये। उनमें पहला कदम तत्काल क्या था कि रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। उसके साथ-साथ निर्यात पर सब्सिडी कम की गई। फर्टीलाइजर पर सब्सिडी कम की गई। और भी क्षेत्रों में इस प्रकार के कदम उठाये गये। आयात की नीति में भी कुछ परिवर्तन किया गया। इंडस्ट्रियल पालिसी में दीर्घकालीन परिवर्तन किये गये। इन सब परिवर्तनों का नतीजा यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपने देश के बारे में विश्वास पैदा हुआ। जब विश्वास पैदा हो गया तो उसके परिणाम-स्वरूप दूसरे देशों के आई.एम.एफ. वर्ल्ड बैंक आदि में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी। यहां तक सुधरी कि जहां पर आपके पास आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी इन कदमों से वह इस लायक बन गई कि अब करीब 11 हजार करोड़ रुपए तक भंडार पहुंच गया है। साथ-साथ यहां का जो रुपया वापस जा रहा था 300 करोड़ रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब से वह रुक गया बल्कि पूंजी निवेश भी होना शुरू हो गया। साथ-साथ देश में जो भ्रम फैल रहा था कि सरकार सोने को बेच रही है, देश के पैसे को उधर कर रही है, जो सोना वहां आर.बी.आई. का रखा गया था उस सोने को वापस ले लिया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वह देश की सम्पति बन गया। उसे रिडीम कर लिया गया। यह जो तीन चीजें हुईं उसके परिणाम-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आपके प्रति विश्वास की भावना फैली। पिछली सरकार के समय में विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया था, कुछ करने को वह तैयार नहीं हो रहे थे उस स्थिति में परिवर्तन में आ गया। अब यह चल रहा है कि इसमें जी.डी.बी. का 6.5 परसेंट जो डेफिसिट है वह कम कर लिया गया। साथ-साथ जो मुद्रास्फीति थी उस पर भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी था। क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो उसका असर साधारण नागरिक पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा, वह महंगाई का शिकार होगा। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना जरूरी था। जो कदम उठाये गये उसके परिणामस्वरूप ही 16 फीसदी इन्फ्लेशन हो रहा था वह घटकर 13 या 12 फीसदी पहुंच गया। औद्योगिक नीति में जो छूट दी गई, उदारनीति जो अपनाई गई उसके परिणामस्वरूप उद्योग की तरफ लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। जो हमारे पब्लिक सेक्टर के उद्योग थे और जो सिक इंडस्ट्रीज थी इनके बारे में कई प्रकार की भावना उठने लगी। जिस टेक्नोलोजी के आधार पर देश के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सफल बनाने का काम और कम्पीट करने का जो मामला है उसको कुशलता के आधार पर प्रोडक्शन बढ़ाने का जो मामला है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत थी। ये जो तीन चीजें थी, कुशलता और प्रोडक्शन में वृद्धि के साथ-साथ इन्टरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए जो चीजें बनी, जो विदेशी निवेश की बात आई तो उनकी तरफ ध्यान दिया गया। अब तो 51 प्रतिशत निवेश होगा और उसके आधार पर जो उत्पादन होगा उसका एक्सपोर्ट किया जायगा। एक्सपोर्ट ओरिएन्टड जब हमारा व्यापार होगा तो इम्पोर्ट भी कुछ कम होगा। इस प्रकार से ट्रेड में जो इम्बेलेंस रह जाता है उस इम्बेलेंस को हम पूरा कर सकें और उसके बाद भी जो हमारा बजटीय घाट रह जाता है उससे और भी समस्यायें पैदा होती चली जाती हैं। हमारी सरकार ने उसको कम करने के लिए कदम उठाये हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : आपकी पार्टी के सब लोग तो वाक आउट कर रहे हैं।

श्री राम नरेश यादव : आप तो समर्थन कर ही रहे हैं । हमारे लोग तो समर्थन करते ही हैं । हमें खुशी है कि विपक्ष ने भी रचनात्मक आधार पर इस दिशा में अब कुछ सोचना शुरू किया है। इसलिए यह जो स्थिति आई है, उसमें एक चीज जरूर आती है और उसकी बहुत चर्चा विपक्ष की ओर से चलती है कि अपनी सावरन्टी को खतरे में डालकर उसको बेचने के लिए आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक के सामने उदारीकरण की नीति अपनाकर सरकार ने घुटने टक दिये हैं । इस देश में जो विदेशी पूंजी का निवेश होगा उसके आधार पर देश खतरे में पड़ जाएगा । जहां तक सरकार का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वह कुछ आदर्शों पर चलती रही है और जब भी देश की राष्ट्रीयता का सवाल आता है या देश की सावरन्टी का सवाल आता है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश का कोई भी नागरिक इस देश की सावरन्टी को ध्यान में रख कर कभी भी अपनी आजादी और देश की आजादी को खतरे में नहीं पड़ने देगा । चाहे वह आर्थिक आजादी हो, चाहे राजनैतिक आजादी हो, इनको वह कभी भी खतरे में नहीं पड़ने देगा । इसलिए इस संबंध में जो भ्रम फैलाने या उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है वह निराधार और निर्मूल है । सावरन्टी को बेचने का और आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक के सामने घुटने टकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है । उसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि जो कदम उठाया गया है और जो बजटीय घाटा कम किया गया है, जो पहले सात करोड़ और कुछ था वह अब पांच करोड़ और कुछ रह गया है । जो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का इम्बैलेन्स था वह भी कम किया गया है । इस तरह से जो सुधारात्मक कदम उठाय गये हैं उन सुधारात्मक कदमों का यह परिणाम हुआ है कि उनका हमारी आर्थिक स्थिति पर अच्छा असर हुआ है । जब हम सत्ता में आये थे उस वक्त जो चिन्ता व्यक्त की गई थी उससे उभरकर नई व्यवस्था से देश को नय माहौल में लाने का काम किया गया है । पहले जो आशंकायें व्यक्त की जा रही थी उन आशंकाओं को सरकार ने निर्मूल कर दिया है। हमारी ट्रेड पालिसी में कार्मस की पालिसी में और इंडस्ट्रियल पालिसी में यह शंका व्यक्त की जाती है कि हमारे पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में जो घाटा चल रहा है उनके बारे में क्या किया जाय । हमारी सरकार भी सोचती है कि आखिर घाटे में चलने वाले उन उद्योगों का क्या किया जाय । इस संबंध में विपक्ष की तरफ से एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जाती है कि कहीं इनका प्राइवेटाइजेशन तो नहीं किया जा रहा है और उनमें जो मजदूर काम करते हैं उनकी छंटनी तो नहीं की जाएगी ? लेकिन हमारी सरकार की यह नीति है कि मजदूरों के हितों पर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं किया जाएगा । सरकार की यह नीति है कि किसी भी कीमत पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा । इसलिए जो सिक यूनिट्स हैं उनके लिए नई टक्नोलोजी और उनके रिस्ट्रक्चर के लिए, फाइनेन्स के लिए और ट्रेनिंग के लिए और उनकी दूसरी जगहों पर व्यवस्था के लिए एक नेशनल रिन्यूअल फण्ड सरकार ने स्थापित करने की शेष की है जसके लिए दो सौ करोड़ रुपयों को व्यवस्था की गई है । एसी स्थिति में जब यह सारी चीजें हो रही हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दिशा में कहीं भी किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और न ही पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने की बात होनी चाहिए । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मजदूरों की छंटनी का भी कोई सवाल नहीं है और न ही उनके हितों पर कुठाराघात करने का सवाल है । सरकार के सामने सवाल यह है कि कैसे इस देश की बढती हुई जन-शक्ति और बेकारी की समस्या को हल किया जाय । सरकार ने इन सवालों को ध्यान में रख कर ही सारे कदम उठाय हैं ।

जहां तक मार्डन टेकनोलोजी का सवाल है, जापान और जर्मनो जैसे देश, जिन्होंने विध्वंस होने के बाद भी नई टेक्नोलोजी के आधार पर अपना आर्थिक विकास किया है, उन्होंने दूसरे देशों से नई टेक्नोलोजी लेकर अपना आर्थिक विकास किया । इसलिए भारत को भी आज की मौजूदा परिस्थितियों में इन्टरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा में आने के लिए, अच्छा माल पैदा कर सके और विकास की गति जो को तेज कर सके, नई टेनोलोजी को अपनाना होगा । अगर उस टेक्नालाजी के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, इसका इस्तेमाल

[श्री राम नरेश यादव]

करके भारत आगे बढना चाहता है तो इसमें सारे देश के लोगों की सहमति होनी चाहिये और इसमें कहीं पर किसी भी तरह के विरोध का सवाल खड़ा न हो, इसीलिये राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में उस नीति का बहुत गंभीरता के साथ समावेश किया है।

इसके साथ साथ एक प्रश्न और खड़ा होता है और वह है कि क्यों कि कृषि और उद्योग ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आधार पर देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक की जा सकती है, जहां एक तरफ उद्योगों में टेक्नालाजी का काम चल रहा है, वहां पर नयी टेक्नालाजी के आधार पर कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में, उत्पादन बढाने, उत्पादकता को बढाने और फिर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम हमारे सामने है। इसी के साथ साथ मार्केटिंग का काम, उसकी व्यवस्था का काम, उसके भंडारण का काम ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ सकते हैं। यहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र खुले हुए हैं, आई.सी.ए.आर. जो है उसके बहुत जगहों पर केन्द्र खुले हुए हैं। य नयी नयी प्रजातियों को जन्म देने का काम करते हैं, उनकी खोज करने का काम करते हैं और खोज के आधार पर किसानों के लिये नय बीज तैयार करने का काम करते हैं। आज इसकी आवश्यकता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने देश के उत्पादन को खपा सकें। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 1947 में अपने चेश की आबादी 34 करोड़ थी जो आज बढकर 85 करोड़ हो गयी है। जहां हम मात्र 51 मिलियन टन अनाज पैदा करते थ वहां आज 17 मिलियन टन पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ देश की बढती हुई जनसंख्या एक समस्या है। कैसे हम इस जनसंख्या पर काबू पायें? अनुमान है 2000 के अंत तक करीब 1 अरब हमारे देश की जनसंख्या हो जायगी और हमें 240 मिलियन टन खाद्यन्न की जरुरत पड़ेगा। इसके लिए आवास का सवाल भी है, शिक्षा भी है, पीने के पानी का सवाल है, उनको काम देने का सवाल है, उनको स्वस्थ रखने की सवाल है। ये सारी समस्यायें आयेंगी। इसीलिय इन तमाम समस्याओं को सामने रखकर हमें कृषि की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसकी तरफ राष्ट्रपति महोदय का ध्यान गया है। इसको करने के लिये कृषि क्षेत्र में जो नये नये औजार हैं, जो नयी नयी तकनीक हैं उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विशेषकर दलहन और तिलहनों का हमारे देश में बहुत ही अभाव खटकता है। हमें दलहन और तिलहन बाहर से मंगाने पड़ते हैं और इसके लिये हमें अधिक विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, विदेशी मुद्रा नहीं है तो फिर हमें इन्हें कैसे बाहर से मंगा सकते हैं। इसलिय कृषि को आगे बढ़ाने के लिय हमें काम करना चाहिये। वसे तो इस समय कृषि क्षेत्र में 8 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हमारी सरकार करती है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है कि कैसे हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। अधिक विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिये देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना आवश्यक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर कृषि क्षेत्र की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिय। इसके लिय बिजली और वाटर मनेजमेंट बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी आई. सी.ए.आर है और जिसके तहत जो आयाल सीड्स के टेकनालाजी मिशन हैं, जो नेशनल डेरी डवलपमेंट बोर्ड है, इनको और विकसित करने की जरूरत है ताकि ये चीजें एक्सपोर्ट ओरियेंटेड हो सके।

इसके बाद जो हमारे यहां ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, जहां पर सूखा पड़ता है, उनकी तरह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल हमारे देश की कृषि का जो क्षेत्र है उसमें से 70 प्रतिशत कृषि का क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है और 30 फीसदी क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिचाई होती है। जो यह स्थिति है, इस स्थिति को ठीक करने के लिये विशेष कार्यक्रम विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। इसके लिए डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम की बहुत जरूरत है। ऐसी जगह पर किस तरह से खेती हो, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमारी सरकार का ध्यान गया है। इसमें सरकार की नीतियों के संबंध में राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में संकेत दिया है जो इस बात का सबूत है कि सचमुच में किस तरह से उद्योग और कृषि को एक साथ रखते हुए दोनों में तालमेल रखते हुए देश में

विकास की गति को तेज करने के लिये जो उचित है सरकार उस तरफ ध्यान दे रही है। कृषि के साथ-साथ उससे उत्पादित होने वाले माल के आधार छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलें, कृषि पर आधारित जो इंडस्ट्री है उसकी ओर ध्यान दिया जाये, कपास है, जूट है, इन सारी चीजों के प्लान्टेशन का काम वहां पर हो। चाय है, काफी है, नारियल है, यह सारी चीजें हैं। इसलिए खती की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यह दोनों क्षेत्र ऐसे हैं। अब प्रश्न यह आता है कि कैसे देश की गरीबी को हल किया जाए। इसी आधार पर पावर्टी एलीवेशन प्रोग्राम लाए जाएं। जवाहर रोजगार योजना, ट्राइसम और आई. आर. डी. पी. हैं, इन सब को एक साथ समेट कर के देश में बेकारी की समस्या को हल करने का काम कैसे होगा, इसके आधार पर कदम उठाने की भी बात है। लेकिन सवाल यह है कि सारी योजनाएं तो हैं, इन योजनाओं का लाभ कैसे लोगों तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे। अब प्रश्न यह है कि कैसे किसान यह समझ सके कि परिस्थिति में उसका उपयोग और उपभोग कसे होगा, उसको कैसे आगे बढ़ा सकें। इसके लिए जरूरी है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करके यह कार्य किया जाए। इसके आधार पर यह काम होना चाहिये, यह भी देश के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले दिनों राजीव जी की सरकार थी। उन्होंने लोकतन्त्र के आधार को मजबूत करने के लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक बिल लाने का काम किया था। उसी तरह शहरी निकायों के विषय में भी एक बिल लाने का काम किया था। सवाल यह था कि जवाहर रोजगार योजना इन्दिरा आवास योजना या अन्य योजनाओं के लिए जो पसा जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे हो, कौन सी मशीनरी है जिसके आधार पर गांव में विकेन्द्रीकरण के आधार पर लोगों को काम मिल सके, रोजगार के अवसर मिल सकें, वहीं पर ही उनका विकास हो सके। सब से जबरदस्त सवाल यह है कि गांव से लोगों का पलायन शहरों की तरफ इसलिए होता है क्योंकि गांव में रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ नहीं होते। इसलिए उस पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन कर के सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात की गई थी। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के मामले में उधर बैठे हुए हमारे साथियों ने बिल को गिरा भी दिया था लेकिन फिर सितम्बर में (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : आप कहां थे यादव जी (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : कर्नाटक एवं केरल पंचायतों के चुनाव की जगह एडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइंट कर दिये हैं आपने, हत्या तो आपने पंचायती राज की की है (व्यवधान) आपकी पार्टी की प्रदेश सरकारों ने की है।

श्री राम नरेश यादव : मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र में जो स्थिति आई है वहां पर बी. जे. पी. और बजरंग दल का सारा समन्वय जो था, वह सारा पर्दा फाश हो गया है (व्यवधान) हम जब सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो सत्ता को लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोआपरेटिव की सारी संस्थाओं को भंग कर के अपनी तरफ से आर. एस. एस. के लोगों को मनोनीत करने का सवाल खड़ा हो गया। यह हम नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार कर रही है। इसलिए इस आधार पर उसको मजबूत करने की जरूरत है जिसकी तरफ संकेत भी है। जो सितम्बर में बिल आया है हमें विश्वास है कि उधर के साथी इस पर चिन्तन करेंगे और इसलिए चिन्तन करेंगे कि सच-मुच में किसानों और गरीबों को जो लोकतंत्र का आधार है, को मजबूत करने की दिशा में उनका जो समर्थन मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया है इसलिए इस बार जरूर अपना समर्थन सरकार को देंगे और उस पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे साथ ही साथ सामाजिक न्याय के लिए भी बहुत कुछ जरूरी था यह बहुत चर्चा होती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो रहा है। पिछली सरकार जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी उन्होंने इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। राजीव जी ने एक विशेष अभियान चलाया था कि जो आरक्षण का कोटा है वह पूरा नहीं हो रहा है। उसको पूरा करने किया जाए। यह लोग नहीं कर सके थे लेकिन इस

[श्री राम नरेश यादव]

सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए कि आखिर वह हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, इनके साथ बहुत दिनों से अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, समाज की मुख्य धारा से उनको अलग कर के रखा गया था लेकिन एक बार जो राष्ट्रीय धारा से उनको जोड़ने का काम हुआ पिछले दिनों जो सारी बातें आई हैं (**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम : गवर्नमेंट आफ इंडिया में एक भी सेक्रेटरी शड्यूड कास्ट का सचिव नहीं है (**व्यवधान**) और न ही किसी निगम का अध्यक्ष।

श्री राम नरेश यादव: प्रश्न यह है कि जगह जगह पर जो बातें आती हैं, आज राजनीतिक जागरूकता है, सम्मान के साथ जीने के भावना है और संविधान से समता और समानता के आधार पर देश को ले चलने का भाव है, इसलिए कुछ जगहों पर तनाव हो जाता है।

श्री ईश दत्त यादव : मंडल कमीशन (आपकी सरकार ने (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव: इसलिए इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष रह गया था। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि एक विशेष अभियान चला करके ऐसे समाज के दलित लोगों के साथ जो एक उत्पीड़न की कार्यवाही होती थी उसको कम करने के लिए एक सम्मान की भावना जगाई। विशेष अभियान चलाने के काम का सरकार ने निर्णय लिया और चला भी रही है। साथ ही साथ एक समाज के लिए जो बहुत अभिशाप था मैला ढोने की प्रथा, मैला ढोने की प्रथा हमारे समाज के लिए अभिशाप थी—मुझे बहुत खुशी है और सदन को भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि इतने वर्षों की आजादी के बाद भी जब कुछ लोग व्यवस्था का एक विकल्प बनाने की कल्पना करके आये थे वे लोग भी नहीं कर सके थे लेकिन इस सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस मैला ढोने की प्रथा को भी समाप्त करेंगे और साथ ही साथ जो उनकी पुर्नव्यवस्था का भी सवाल है तो उनकी पुर्नव्यवस्था के लिए उनकी जीविका के लिए ताकि उनका नुकसान न हो जाए, कुछ व्यवस्था करेंगे जिससे जीविका का साधन उन्हें मिले इसमें कई लाख लोग लगे हुए हैं। जो संविधान की धारा 46 है जिसमें "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।" कहा गया है, इस आधार पर जो कांस्टीट्यूशन की 292 वीं धारा है उसके अंदर इस संबंध में कानूनी व्यवस्था करने का प्रावधान है साथ ही साथ साथ सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में बहुत कुछ ढिंढोरा पीटा गया था। महोदया मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई थी तो उन्होंने बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का कोई इरादा नहीं था यह केवल एक राजनैतिक सोच के तहत, जो सामाजिक सद्भाव था उस सद्भाव को बिगाड़ने के लिए, उस समय जो इनके अंदर का आंतरिक द्वंद्व था जो विघटन की प्रक्रिया शुरु हो गयी थी (**व्यवधान**)... उस प्रक्रिया के फलस्वरूप उन्होंने कुछ सदन में घोषणा करने की बात की थी (**व्यवधान**) वह पोलिटिकल गिमिक था। इसलिए मैं कह रहा हूं महोदया कि 13 अगस्त को, बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि 13 अगस्त को जब यहां पर रखा जा रहा था सदन के पटल पर, माननीय सदस्यों को यह बताया जा रहा था कि हम इस आरक्षण को 27 फीसदी लागू करेंगे, प्रश्न यह था क्योंकि इसमें पैरा 3 में एक वाक्य लिखा हुआ है: "सच लिस्ट इज़ बींग इश्यूड सेपरेटली", 13 अगस्त को कहा, "सच लिस्ट इज़ बींग ईश्यूड सेपरेटली", तो महोदया मैं कहना चाहता हूं कि यही वह स्थान था, यही वाक्य था जिस वाक्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सालिसिटर जनरल ने बहस की कि आखिर यह लागू किस पर होगा, जबकि कोई लिस्ट बनी ही नहीं है। अगर सचमुच में लागू करने का इरादा था तो लिस्ट पहले तैयार की जाती,

बताई जाती देश की जनता को, पिछड़े वर्ग के लोगों को बताया जाता कि हमारी यह लिस्ट है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है या स्टेट लिस्ट में जो कामन है, कौन सी लिस्ट है, जब तक यह नहीं घोषित किया जाता तब तक जो आप लोग कोरा ढिंढोरा पीटते रहे, नारा देते रहे हैं पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करते रहे हैं अब यह काम चलने वाला नहीं था। यह थोथा नारा ही था। इसलिए यह कहना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं, इधर बैठे हुए लोगों को (व्यवधान) ... सुप्रीम कोर्ट में हमारी गवर्नमेंट पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकती, न उनके साथ कोई ज्यादती कर सकती है। जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना संविधान में है, हमने घोषणा पत्र में भी कहा है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके आरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध है और पहले भी जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी उनमें लागू किया गया था, दक्षिणी राज्यों में किया गया था। इसलिए कहीं पर उनके साथ अन्याय करने का सवाल नहीं है। बधाई देनी चाहिए आप लोगों को इस सरकार को कि उस काम को भी आप नहीं कर सके जिस काम को करना चाहिए था। इस सरकार ने उसे कर दिखाया। एक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम बना दिया जाता तो किसका फायदा होता। लेकिन केवल नारेबाजी में, थोथे नारों और घोषणाओं में बात रह गयी। सड़क पर लाकर पटक दिया, न किसी को मिल पाया न किसी को जा पाया बल्कि जो सामाजिक सद्भाव था, सौहार्द था उसमें आघात पहुंचाने का काम उस समय हुआ। 21 फरवरी को जब राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसमें जिस पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम बनाने की घोषणा की संकेत था आज वह पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम बन गया है। दो सौ करोड़ रुपया इसमें रख भी दिया गया है। यह इस बात का सबूत है कि सचमुच में कांग्रेस पार्टी और सरकार किस तरह से इस सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के

3 P.M.

साथ न्याय करना चाहती है। साथ ही साथ समाज के ऐसे लोग जो कि दूसरे वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी चाहती है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, कहीं पर आपस में टकराव न हो और सड़कों पर आ करके आपस में लड़ने का काम न हो, क्योंकि राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। इसीलिए हमने यह भी फैसला किया है कि समाज के उन लोगों के लिए भी 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की व्यवस्था की जाएगी लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पैंडिंग है। इस लिए जब तक पैंडिंग है तब तक उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सरकार और हम उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : गवर्नमेंट डिसीजन तो ले सकती है।

श्री राम नरेश यादव : गवर्नमेंट डिसीजन न लिया होता तो जवाब कैसे देता। ... (व्यवधान) डिसीजन ले लिया है गवर्नमेंट ने तो यह जवाब दिया है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ... (व्यवधान)

इसलिए महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी क्योंकि सब लोगों का साक्षर होना, शिक्षित होना आवश्यक है, महिलाओं पर होने ... (व्यवधान) महिलाओं के प्रति न्याय दिलाने के लिए, इन सारी चीजों का विस्तृत उल्लेख है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रश्न को जो भी चुनौतियां हैं, महिलाओं को सामाजिक न्याय मिले, उनको समाज में उचित स्थान मिले इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है। उसके साथ-साथ जो विदेश नीति है उसमें भी जो गुटनिरपेक्षता का आंदोलन था जिसकी पं0 जवाहर लाल नेहरू ने शुरुआत की थी इंदिरा जी भी उस पर चलती रहीं राजीव जी ने जिसको आगे बढ़ाने का काम किया है वह हमारी विदेश नीति का आधार है। लोहिया जी भी ... (व्यवधान) लोहिया जी की दृष्टि पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे बने रहें हमेशा यह रही है इसलिए पाकिस्तान बंगला देश की बात

[श्री राम नरेश यादव]

करते थे और आज भी ठीक वही जबकि पाकिस्तान के मामले सारे काश्मीर में तनावपूर्ण हैं इसके बावजूद भी हमारी सरकार प्रधान मंत्री उनसे बात भी कर रहे हैं। आखिर इससे अधिक उस रास्ते पर चलने के अलावा दूसरा हो क्या सकता है। इसलिए सारी चीजों पर गंभीरता के साथ बहुत विस्तार से चर्चा की गई है लड़कों के विकास के लिए और अगले आने वाले दिनों में किस तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाए, रोजगार के अवसर कैसे आरंभ किए जायें ये सारी चीजें हैं।

महोदय, मैं इन शब्दों के साथ हमारे उधर के साथी बैठे हुए हैं विशेष करके बी.जे.पी. के लोगों से कहना चाहता हूं कि देश आपका भी है और आप इस देश के निवासी हैं आप इस तरह की यात्रायें करके लोगों के मनों को तोड़ने का काम न करें, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द टूटे। उसी तरह से दूसरे साथियों से भी कहना चाहता हूं जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई थी और अब वह जिस तरह से सुधरी है, आप भी आइए, मैंने पहले कहा था कि चुनौती है, अब अवसर मिला है, इसलिए चुनौती को ध्यान में रखते हुए अवसर ठीक से इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASKAR ANNAJI MASODKAR): Shri Hanumanthappa to second. Please be brief.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): I will not encroach upon your time.

Sir, I rise to support the Motion of Thanks moved by my esteemed colleague, Shri Ram Naresh Yadav, to the honourable President for his Address delivered to the Joint Session of Parliament on the 24th February, 1992.

Mr. Vice-Chairman, Sir, even though this practice is inherited by the British Parliament, the Constitution makers deliberately retained this provision inasmuch as the Presidential Address will be a bird's eye view of the year that passed and will throw light upon the year which is ahead. It is neither a progress report nor a policy statement, but it certainly throws light on the achievements as well as the programme of action of the Government in the days coming ahead. Sir, before I go to the exact subject, let me say one thing. What is the situation that this new Government inherited when it took charge of the country? Sir, you may remember this Government took charge of this country when the whole country was bewildered, was shocked by the dastardly assassination of our beloved Rajiv Gandhi, Political pandits as well as the external world were doubting the very existence of India as a nation. The people were doubting whether India can stand as a nation, as a united nation. And they were expecting that India will be disintegrated in the absence of the towering personality in the political scene. But it is the sagacity of the Indian voter, the voters of this country who of late thought and entrusted this responsibility of leading the country to the Congress Party, and the Congress, much to the disappointment of our Opposition friends, could be able to stand united and select Narasimha Raoji to lead the Party and the Government. Sir, this is about the political situation when we took charge. And the economic situation was actually the action and the inaction of the previous Government...

AN HON. MEMBER: Governments.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Yes, the two successive non-Congress Governments that preceded our Government.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): One was your creation.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: One was your creation. (*Interruptions*) Sir, they had left the national economy in a shambles. Our balance of payment situation became precarious. (*Interruption*)... When Yashwant Sinhaji handed over to us.

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): What was the position when Rajiv Gandhi handed over?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Digvijay Singh, if you want those figures also, I am ready with them. I have got the figure of what we handed over.

SHRI DIGVIJAY SINGH: I will be the happiest man if you give that figure.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I will give you, if you want.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please, let us not have cross-talk.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: What you took-over, you know better. Unfortunately, you took-over from Mr. V. P. Singh and not Mr. Rajiv Gandhi. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Hanumanthappaji, you please address the Chair.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Mr. V. P. Singh was the Finance Minister of Mr. Rajiv Gandhi. (*Interruptions*).

SHRI H. HANUMANTHAPPA: All right, I will give you only one figure. When you took-over, the balance of payments position was Rs. 6,000 crores. When you handed it back, it was Rs. 2,000 crores. I stop at this. And I go further. (*Interruption*). You wanted what Mr. Rajiv Gandhi entrusted to you. I have given the figure. If you want the details, I do not want to waste the time. You know very well. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You please address the Chair. There should not be a cross-talk. You address me. That is all.

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, the debate is lively. We are enjoying it.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, actually, when a man is in an economic crisis, he starts selling his immovables first, then movables and at the last when he has nothing to sell, he touches gold which has been respected and honoured and which is dearer to his sweet-heart.

SHRI R. K. DHAWAN (Andhra Pradesh): I think, you should change the order—movables, immovables and gold.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: All right, movables, immovables and gold. But Yashwant Sinhaji did not spare even that gold.

SHRI YASHWANT SINHA: And what you did?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: This proved to the people of this country that whenever a non-Congress Government takes over this country, whether in 1977 or 1989 or 1990, the country's economy is in a shambles, and they either sell or mortgage the gold. This is the historical truth.

SHRI YASHWANT SINHA: Whose Finance Minister is Mr. Manmohan Singh?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Yashwant Sinhaji has to wait for some time. I will come to that aspect. At whose behest was Mr. Yashwant Sinha acting and on whose dictates he has acted, I will come to that later.

NRI deposits were being withdrawn. Therefore when this Government came to power, it had to take certain hard steps and we know how the situation was. Mr. Narasimha Rao took the reins of this Government with this resolve, that the economy is in a crisis. Here I would like to quote from his speech. "The balance of paymtnt situation is exceedingly difficult. Inflationary pressures on the price level

[Shri H. Hanumanthappa]

are considerable. There is no time to lose. The Government and the country cannot keep living beyond their means and there are no soft options. We must tighten our belt and be prepared to make the necessary sacrifices to preserve our economic independence which is an integral part of our vision for a strong nation. In the pursuit of this objective, the Government attaches the highest priority to the preservation of the health of the economy."

In order to improve the health of the economy, the Government has formulated the new economic policy, the industrial policy as well as the trade policy, making it more liberal, giving more attractions to foreign investments and making the exports easy and allowing essential things to come into the country, which would take care of this financial crisis. The result, as it is, has yet to come. We cannot expect economic results within a short time; it takes a long time. But still the position is that as on today, we have the reserves of Rs. 11,000 crores. Anyway. I do not want to take more time of the House.

Coming to law and order situation, after this Government took over, we passed a legislation to maintain the position of the places of worship as it existed on 15th August, 1947, and we have accepted that the Mandir-Masjid differences should be resolved either by negotiations or by the court verdict. About reservations under Mandal Commission's recommendations, we are waiting for the Supreme Court's decision.

Handling of the *Ekta Yatra* is one shining example of the Congress Government. There was the *Rath Yatra* from Somnath to Ayodhya, of 3000 Kms. which resulted in more than a thousand deaths, arrest of a leader of a political party and the fall of a Government. It resulted in the fall of the National Front Government. But see the way this *Ekta Yatra* from Kanya Kumari to Kashmir was handled by the Congress Government... (*Interruptions*). I think the BJP will have a chance to answer. In spite of the much publicised *Yatra* from Kanya Kumari to Kashmir—such a long route—there was not a single life lost. The BJP wanted to take mileage from this much publicised *Yatra* which was a politisal *Yatra* rather, Why I call it a political *Yatra* is, and I want to go on record, if Shri Murli Manohar Joshi had really undertaken this *Yatra* for *ekta*, he should have known the culture and the structure of the society of India. Indian society does not comprise Hindus alone; it consists of Muslims, Christians, Buddhists, Jains and Parsees, everybody. But while starting on his *Ekta Yatra*, Shri Murli Manohar Joshi deliberately visited only Hindu temples plus against the threat of AK-47, he visited Gurudwaras but he deliberately avoided Masjid dargah or church or a Jain temple or a Buddha temple stupa. So, it was not *Ekta Yatra*; it was a political gimmick of the BJP in the name of *Ekta Yatra*. And the way of handling of this *Yatra* exhibited the sagacity of this Government I have already given a comparison between the handling of the *Rath Yatra* by the National Front Government and the handling of the *Ekta Yatra* by the Congress Government. What is the effect of these efforts our endeavour, to restore the economic health, to contain the law and order situation, etc? Usually, whenever there are by elections to Parliament, it is the Opposition that gains. The seats are usually won by the Opposition. But this time, what happened? Out of the 15 seats for which byelections were held, eight went in favour of the Congress (I).

Secondly, we had the Punjab elections. We got twelve out of the thirteen seats, plus a Government there.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Plus ten per cent vote.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Thirty per pent. (*Interruptions*) Even that you could not do.

SHRI DIGVIJAY SINGH: I have done, my friend. Your Government stopped the election process just before twenty four hours.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You answer when your turn comes.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Digvijay Singh, your party has been de-recognised.

SHRI DIGVIJAY SINGH: So what, Mr. Narayanasamy? It is the people who matter in a democracy. (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Mr. Narayanasamy, when you recognised tha party, that party was not born. (*Interruptions*)

SHRI R. K. DHAWAN: This only shows we believe in democracy. We are not like your party. Your party does not allow other parties to flourish.

SHRI V. NARAYANASAMY: We recognised even an unrecognised party.

SHRI YASHWANT SINHA. He is doing it because of the river water dispute Mr. Narayanasamy does not want him to speak because of the river water dispute.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Actually, it is only Mr. Yashwant Sinha who is trying to fish in troubled waters.

SHRI YASHWANT SINHA: You are too big a fish to catch.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Dipen Ghosh does not want to give credit to Mr. Digvijay Singh. He wants to take it on himself, in regard to Punjab. His Prime Minister, when his party was a partner in that Government, went to Punjab, saying 'I am going there as a friend of the Punjabis'. He went there in an open jeep, without security, but there were security people in civilian dress.

AN HON. MEMBERS: Two hundred people.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: We all know this. Still, they were unable to infuse confidence in the people of Punjab. This only shows the people of Punjab are with whom.

SHRI DIGVIJAY SINGH: He was a sleeping partner. His party was a sleeping partner, not an active one.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, the State from which you come, namely, Maharashtra, has given all the Zilla Parishads—29—in favour of the Congress (I). All the important municipalities and all the panchayats have gone to the Congress (I), (*Interruptions*).

SHRI DIPEN GHOSH: All the dadas in Bombay have joined the Congress (I). (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: What about the Calcutta *dadas*?

SHRI DAYANAND SAHAY (Bihar): *Dada* is a respetable word in West Bengal.

SHRI DIPEN GHOSH: In West Bengal, not in Bombay.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, this reflects the attitude of the people of this country, how they view the Congress (I) rule. I want to put on record. After all, we have to go by the directions of our masters. We have to satisfy our masters. Our masters are neither Mr. Dipen Ghosh nor Mr. Yashwant Sinha. Our masters are the voters, the people of this country. They have put us in power. We have made certain promises to them in our election—manifesto. We are answerable to it. How can my friends, sitting on the other side, search for results from their manifesto? It is not possible. They will not be able to get the results to our actions from their manifesto. How can they search their manifesto and ask us why we have not done this, why we have not done that? We have to go by our manifesto which we gave to the people, depending upon which the people have voted us to power.(*Interruptions*) Mr. Dipen Ghosh you have nothing but the World Bank. I will come to that. Please wait, (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir they are unnecessarily interrupting Mr. Hanumanthappa. They are not allowing him to speak.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, may I just say some thing?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHAŞKAR ANNAJI MASODKAR): Let him complete.

SHRI ASHIS SEN: I was only saying that they have changed their masters from voters to Washington.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am coming to that. Unfortunately, I am being disturbed. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That means, you are making an effective speech.

SHRI DIGVIJAY SINGH: At least lively.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am coming to Kashmir.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Don't go. Shri Murli Manohar Joshi has already gone. (*Interruptions*)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Please appreciate my point. I am not on that line. I do not claim any credit that we have done, we have achieved much in Kashmir, but we have been able to awaken the world community regarding the Kashmir issue. When there was a threat across the border, we were able to awaken the European community to rise to the occasion and pressurise Pakistan not to indulge into such activities. This is a positive step and a positive approach this Government has taken and it has received a positive response from the outside world.

Coming to Assam, we had to deploy army in September 1991. Some ULFA activities have been arrested, some arms have been seized, some have surrendered themselves and some are ready for talks. We will continue our efforts to normalise the situation.

Very much wanted by BJP and expected by Delhi we have been able to pass the Delhi Legislative Assembly Bill also. Let us see the world scenario as it is developing. Russian disintegrated itself. The second world power has vanished. Now the responsibility lies upon the third world.

SHRI R. K. DHAWAN: Do not say 'Russia'.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: The USSR disintegrated itself into small Republics and now there is only one world power left and that is the USA, (*Interruptions*) So, the entire third world is to king towards India which has to take a position of leadership. India has already achieved onerous position in leading the third world as against the single world power, in the absence of the second world power that has disintegrated itself. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You make your own point. Why do you get disturbed? You go ahead.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: India may not give it to America, but unfortunately, Shri Hanumantha Rao and Shri Dipen Ghosh have lost their...

SHRI DIPEN GHOSH: Whom?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You have lost the one from whom you were drawing inspiration. Actually, the integrated USSR claimed communism to be...(*Interruptions*). You are also disturbing.

The second aspect is, the other source from where you were drawing inspiration, was China. Unfortunately for them and fortunately for us, China's Premier has visited India. We are friendly, we are discussing and we are coming to a close... (*Interruptions*). I do not know, I have to tell geography to Shri Digvijay Singh. Nehru was born in India.

SHRI DIGVIJAY SINGH: I said, "Nehru Bhawan, Hanumanthappaji".

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, in this background, I just appeal to my friends on the other side: you have got every right to criticise the Government, but not by belittling the achievements, which will bring down India in the eyes of the world body. This is where I want to appeal to you. India has to develop as a leader of the third world and has to take

the onerous responsibility in the absence of the second world power. There we have a certain responsibility about the image and the credibility of the country outside.

Sir, coming back, my friend, Mr. Dipen Ghosh was very much.....

SHRI DIPEN GHOSH: Dipen Ghosh has not yet spoken. How can you reply to his points?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I know. I am not replying. I am only answering to your interest.

Actually they say, "World Bank, World Bank, World Bank." Shri Manmohan Singh has disarmed all the Opposition parties. Actually they have to depend on "the World Bank and the IMF" to criticise the Budget of Shri Manmohan Singh. Except "the World Bank and the IMF" they have no ammunition. The gun powder is lost. (*Interruptions*).

I will come to that. More than me, Mr. Yashwant Sinha knows it because he is the author of the whole thing. (*Interruptions*) He is the man who approached the World Bank first before this Government came over here. He wrote the letter to the World Bank. We have only followed that. If this Congress Government is accused of selling away to the World Bank or the IMF, the first responsibility is.....

SHRI DIPEN GHOSH: That means your Government is an extension of his Government.

SHRI YASHWANT SINHA: Actually Mr. Manmohan Singh is our plant.

SHRI DIPEN GHOSH: His Government came with your support. Now you say that your Government is an extension of his Government. (*Interruptions*)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Whatever it is, you are responsible for it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Hanumanthappa, you have to second the Resolution.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am seconding it.

8 R.S.—11.

SHRI DIGVIJAY SINGH: He has to go to Kashmir.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: *Hogaya* I am not going to Kashmir now.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Cauvery come to Cauvery. I am supporting you.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Not necessary. We will settle, myself and Mr. Chidambaram. You need not come there. It is our internal thing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Hanumanthappa, you please complete now, complete the seconditg now. (*Interruptions*).

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, the recent Budget that has been placed my friends may be reading, Except the bias—"bias" I underline—right from the common man to the businessman to the industrialist to the service personnel, everyone has welcomed this Budget.

SHRI DIPEN GHOSH: Eldorado? (*Interruptions*).

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Whatever it is, even the critics of the Congress have appreciated the Budget.

SHRI DIPEN GHOSH: By seconding, he is already initiating the discussion on the Budget. Is it so?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: In the given situation, this is what we were able to do from the day we took over the Government. This is what we were able to do the last day when we took over the Government. I don't want to initiate the discussion on the Budget. While concluding I go back to the Presidential Address itself and I quote from it:

> "India is on the threshold of taking rapid and purposeful strides into the future. Conditions are being created so that there is an acceleration in the pace of development, our people can enjoy a better quality of life and India can hold her own in a rapidly changing world. The present is full of challenges as well as opportunities. Let us not shy away from treading new paths. Let us be

[Shri H. Hanumanthappa]

bold and innovative in our approach. The hardships of the present are only the harbingers of a brighter future. But even as we move into the future, let us be disciplined and resolute in our approach. Let us shun acrimony for dialogue, violence for amity lest we be deflated into the by-lanes of history."

With these words of the President, I second the Motion moved by Ram Naresh Ji to thank the President for his Address delivered to the Joint Session of both Houses of the Parliament.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The Motion has been properly moved and seconded.

There are exactly 567 amendments to this Motion, which I shall call one by one. There are a group of hon. Members standing by certain amendments. So, I will call the first name. If there is any difficulty, I will call the other name.

Amendments No. 1 to 6. S/Shri Jagdish Prasad Mathur, Kameshwar Paswan, Sangh Priya Gautam, Ramdas Agarwal, Krishan Lal Sharma, Ashwani Kumar, Raghavji—Not present. Amendments not moved.

Amendments Nos. 7 to 23. Smt. Sushma Swaraj, S/Shri Anantray Devshankar Dave, Gopalsinh G. Solanki—not present. Amendments not moved.

Amendments Nos. 24 to 29.

SHRI SHIVPRASAD CHANPURIA (Madhya Pradesh): Sir, I move:

24. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about raising the royalty on coal and other minerals, keeping in view the backwardness of the State of Bihar."

25. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the strict enforcement of laws to check the menace of air and water pollution."

26. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the concrete steps to be taken to solve the complex Cauvery water issue to the satisfaction of all concerned."

27. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any action plan to meet the threat posed by Pakistan's know-how to acquire nuclear capacity."

28. That at the end of the Moiton, the following be *added*, namely:—

'but regret that the Address does not mention about Government's intention to solve the Kashmir problem which is threatening the national unity."

29. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the action plan for national unity as well as cultural and emotional integration of the country."

SHRI DIPEN GHOSH: Sir I move:

30. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government has failed to implement the Rajiv-Longowal Accord and bring about a just and amicable solution to all outstanding issues in Punjab."

31. That at the end of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government has failed to contain extremist and

separatist activities in Jammu and Kashmir and to bring about normalcy in the Valley.

32. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the changes made by the Government in the indsutrial, fiscal and trade policies have resulted in the erosion of country's economic sovereignty and abandonment of the principle of self-reliance."

33. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government's new industrial policy has resulted in the further lowering of industrial growth rate leading to recession, opening of India's domestic market to Western multi-nationals and creating problems for small scale industries and further squeezing of employment opportunities."

34. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the changes in the trade policy and devalution of Indian rupee have resulted in the reduction of country's export-earning in Dollar terms."

35. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the creation of National Renewal Fund for executing its Exist Policy and Government's decision to wind-up and frume the work of several Central Government offices and abolition of posts would result in large scale retrenchment of workers and employees."

36. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government's resorting to administered price rise and adopion of certain other policy decisions have resulted in the rise in prices of all esential commodities and stepped up nflationary pressures."

37. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the economic policy changes initiated recently by the Government have reulted in a decline of country's GDP."

38. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government's policy to allow participation of private sector in several infrastructural areas like power, steel, airlines, shipping, railways, telecommunication, defence production and disinvestment in the public sector upto 49 per cent would cause erosion in the position of commanding heights which the public sector has in the country's economy."

39. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government has failed to reject the Dunkel proposals which would lead to penetration of multi-nationals in the fields of agriculture, research, science and development' and affect the country's interest."

40. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government has failed to bring about a negotiated settlement of sharing and allocation of waters of inter-State rivers between the States."

[Shri Dipen Ghosh]

41. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government's announcement of policy decision to allow disinvestment in public sector upto 49 per cent and privatise the work of the Government establishments like railways, defence, telecommunications etc., would cause substantial shrinkage in the job opportunities for SCs/STs in Government Establishments and Public Sector Enterprises."

42. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government orders to increase the prices of rice and wheat distributed through Public Distribution System and failure to bring more articles of daily necessity under PDS have substantially weakened the PDS, as such, resulting in further addition to the miseries of the common people."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments Nos. 43 to 50. Shri Narayan Kar. Not here. Amendments and moved.

Amendments Nos. 51 to 61. Dr. Jinendra Kumar Jain. Not here. Amendments not moved.

Amendments Nos. 62 to 74. Shri Sangh Priya Gautam. Absent. Amendments not moved.

Amendments Nos. 75 to 77. S/Shri Anantray Davshanker Dave and Gopalsinh G. Solanki. Not here. Amendments not moved.

Amendments Nos. 78 to 80. S/Shri Gopalsinh G. Solanki and Anantray Devshanker Dave. Not here. Amendments not moved.

Amendments Nos. 81 to 97. Shri Sunil Basu Ray.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Sir, I move:

81. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the measures taken to restore normalcy in Kashmir."

82. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the abduction of a Russian Technician in Assam and his subsequent fate."

83. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to state that the hard decisions taken by Government are motivated by the World Bank/IMF and that the new Industrial Policy is designed to open the doors to foreign capital, promote Indian Monopoly Capital, encourage Exit Policy, dismantle Public Sector, throw lakhs of workers/employees out of employment and to reduce the scope of employment."

84. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of Government to implement the recommendation of the National Commission on Rural Labour."

85. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the impact of the Dunkel proposals and Government's inability to take strong protective measures to defend national economic sovereignty."

86. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of Government to promote tourism for all sections of people."

87. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the measures taken to implement total land reforms as mardated by the Constitution."

88. That at the *end* of the Motion, the the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the inability of the Government to assure Agriculture freedom from the vagaries of nature."

89. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to state that he Cauvery continues to flow as a River of Discord."

90. That at the *end* of the Motion, the following bt *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to provide jobs social security, housing, water, health, education, good environment to the economically and soctally down-trodden people."

91. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the measures taken to abolish the practice of manual carrying of night soil and rehabilitation of the people engaged in this work."

92. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the measures taken to protect and promote the basic interest of SC|ST people by providing them with jobs and necessary financial support."

93. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the steps taken to protect the minorities.

94. That at the *end* of the Motion, the folowing be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the steps taken to promote the interests of the women."

95. That at the *end* of the motion, the following be *added*, nameiy:—

"but regret that the Address fails to mention about the steps taken to strengthen the Public Distribution System."

96. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the steps to control and bring down inflation, price rise and to restore value of Rupee."

97. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to fallow the Non-Alignment Policy."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments Nos. 98 to 101. Dr. R. K. Peddar. Absent. Amendments not moved. Amendments Nos. 102 to 111. Shri Ranjit Singh Absent. Amendments not moved.

Amendments Nos. 112 to 124. S|Shri Jagdish Prasad Mathur, Krishan Lal Sharma, Sangh Uriya Gautam. Absent. Amendments not moved.

Amendments Nos. 125 to 130. S|Shri Krishan Lal Sharma, Sangh Priya Gautam, Jagdish Prasad Mathur, Smt. Sushma Swaraj Absent. Amendments not moved.

Amendments Nos. 131 to 144. Shri Ram Jethmalani and Sardar Jagjit Aurora. Not here. Amendments not moved.

Amtndment No. 145 Shri J. S. Raju SHRI J. S. Raju (Tamil Nadu): I move:

[Shri J. S. Raju]

145. That at the *end* of the Motion the follwing be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not spell out a dead line by which the backlog of vacancies reserved for SC and ST Communities in Government departments|Public Sector Undertakings and Banks will be filled up."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments Nos. 146 to 154. Shri E. Balanandan.

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Sir, I move:

146. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the serious flaws in the recent elections in Punjab in which 75 per cent of the people did not participate."

147. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of the Government to take steps to implement the Rajiv-Longwal Accord in order to involve large majority of the Punjab people in the electoral process."

148. That at the *end* of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the help provided by the Government to the BJP leaders to reach Srinagar to hoist the national flag which resulted in the workening of the situation."

149. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about recent move by the Uttar Pradesh Government to construct a boundary wall around the notified area near the Temple Complex at Ayodhya which includes the disputed site."

150. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to note the adverse impact of the changes being made in the industrial, financial and trade policies of the Government which are resulting in the weakening of the process of self reliance de-industrialisation and foreign multi-national-domination in our industrial financial and trade sectors."

151. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the adverse impact of the unrestricted permission given to the foreign multinationals to penetrate into our industrial sector thereby rendering our established indigenous capacity idle, causing severe erosion in the R & D base built over the years and making the skilled manpower remain practically unutilised."

152. That at the end of the Motion, the following be *added*, *namely*:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to protect employment and the growing attempts being made to send out of employment, millions of workers from various industrial and service sectors."

153. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of Government to bring back the prices to the level of July, 1990."

154. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the policy of raising the administered prices of daily necessities like rice and wheat, which has created upward swing in prices."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments Nos. 155 to 162. Dr. G. Vijaya Mohan Reddy.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir I move:

155. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely,—

"but regret that the Address does not mention about any effective action plan to solve the growing problem of starvation deaths among handloom weavers in the country."

156. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any integrated action plan to check the deteriorating law and order situation in several parts of the country."

157. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely,—

"but regret that the Address fails to indicate any definite time frame to introduce legislation for comprehensive electoral reforms."

158. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely,—

"but regret that the Address fails to mention about any effective measures proposed to be taken to bring down the prices, particularly of consumer goods for providing relief to the people."

159. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely,—

"but regret that there is no mention in the Address about any action plan to meet the threat posed by Pakistan's know-how to acquire clear capability."

160. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely,—

"but regret that the Address does not mention about any effective action plan to solve the growing problem of population explosion in the country."

161. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely,—

"but regret that the Address does not mention about any effective action plan to prevent the interference of IMF and World Bank in the financial policy of our Government."

162. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely,—

"but regret that the Address does not mention about any effective action plan to solve the crisis of petroleum and petroleum products in the country."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments No. 163 to 167. Shri Mentay Padmanabham, Dr. Narreddy Thulasi Reddy, Dr. Yelamanchili Sivaji Smt. Renuka Chowdhury. Not here. Amendments not moved.

Amendments Nos. 168 to 177. Shri Ashis Sen.

SHRI ASHIS SEN: Sir, I move:

168. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely,—

"but regret that the Address fails to mention that no step whatsoever has been taken by Government to implement the Rajiv-Longowal Accord in relation to the State of Punjab."

169. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely,—

"but regret that the Address does not mention that Government have not taken appropriate measures to create the necessary climate for the safe return of the distressed migrants from the Kashmir Valley to their respective homes."

170. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely,—

"but regret that the Address does not mention that our foreign exchange

[Shri Ashis Sen]

reserves today computed at 10,000 crores in rupee currency is only national and there is no material improvement in terms of foreign currency so as to feel assured and that the overall economic policy has led to borrowing of billions of dollars from the IMF and the other Agencies which could have been avoided had the alterate policy proposed by various economists and West Bengal Government been considered by Government."

171. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely.—

"but regret that the Address does not mention that more than 250.000 industrial establishments have been closed and lakhs of workers rendered jobless."

172. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely.—

"but regret that the Address does not state that the new industrial policy and the Exit policy will accentuate the unemployment position further."

173. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely.—

"but regret that the Address does not mention that Government's line of approach is that the public sector undertakings should heavily reduce their work force at least to the extent of 40 per cent and that the General Insurance Corporation has already issued a notification aming at superannuation of its staff prematurely at the age of 50 years and that several departmental establishments of the Central Government have been directed to be closed down find that proposals are afoot for drastic reduction of officers and other stac in all Government Departments and for stopping any recruitment and promotion of staff.55

174. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not say that measures to increase the representation of those belonging to Scheduled Castes Scheduled Tribes in Government, Public Sectors and Banks, though necessary, will not by themselves help remove their age-old disabilities unless comprehensive efforts are made to economically and socially uplift these entire sections of our people for which precious little has been done by Government."

175. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to indicate that notwithstanding the time to time proposals made by Government to strengthen and improve the Public Distribution System, this has not reached a take-off stage on all-India level and that wherever the PDS by still working is severely affected by inadequate supplies from the Centre and that no step has been taken to supply various other essential articles through these outlets at fair price rates to push down the general price level."

176. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to give a warning signal about the serious dangers inherent in the US Act Super 301 and the move the Intellectual Property Rights for which the USA has been putting pressures to the detrement of our scientific research work in the fields of agriculture, pharmaceuticals and so forth."

177. That at the *end* of the Motion. the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the Report of the High Power Committee on Financial System (Narasimhan Committee) whose recommendations are detrimental to the interests of the people and the

country's financial system e.g. (a) gradual privatisation of the nationalised banks and other financial institutions by a process of disinvestment of shares, (b) free entry to more and more foreign banks into the country which will severely hit the indigenous banks and the expansion of their activities, (c) slashing down of priority sectors social lending from the present 43 per cent—44 per cent to 10 per cent of the total credit allocation thus drastically reducing the benefits accuring to the underdeveloped areas and the rural poor by the services rendered by rural branches and Regional Rural Banks and thereby negating a major objective of bank nationalisation, (d) restructuring of the banking system in a way that subserves the interests of monopolists, (e) virtual withdrawal of Reserve Banks's powers to inspect banks, (f) Selling of banks' non-performing assets at a substantial discount to a new agency (Assets Reconstruction Fund) without directing disclosure of the names of the large defaulters who do not repay the loans and advances taken nor the interest thereon, (g) encouragement to winespread growth of Mutual Funds which leads to diversion of banks deposits to speculative market, (h) unrestrained massive computerisation mechanisation of banking operation in non-essential areas to create surplussage of staff and consequential retrenchment."

SHRI SUNIL BASU RAY: Sir, I move:

178. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret the Address does not mention about any effective measures to solve the growing problem of unemployment amongst the youth of the country."

179. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the execution of an effective action plan on priority basis to remove the increasing imbalance in the development of different regions in the country."

180. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about any effective measures proposed to be taken to check the continuously rising trend in the prices of essential commodities and consumer goods."

181. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about any positive plan for improving the living standard of agricultural labourers in the country."

182. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any effective measures proposed to be taken to check the growing incidents of violence during elections in the country particularly in the Northern parts of the country."

183. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the steps to be taken for promoting cottage and handloom industries and providing necessary economic assistance in rural areas for this purpose."

184. That at the *end* of the Motion, the follofing be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about any action plan to augment water supply in Delhi especially during summer seasons."

185. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention Government intention to

[Shri Sunil Basu Ray]

rehabilitate the slum-dwellers in big cities."

186. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the enforcement of laws to check the menance of air and water pollution."

187. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the National Renewal Fund which has been created for executing its Exist Policy and Government decision to wind up and prune the work of several Central Government offices and abolition of posts which would result in large scale retrenchment of workers and employees.

188. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the Government's policy to allow participation of private sector in power, steel, airlines, shipping, railways, telecommunication, defence production and disinvestment in the public sector upto 49 per cent which would cause erosion in the position of commanding heights which the public sector has in the country's economy."

189. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government has failed to reject the Dunkel Draft proposals which would lead to penetration of multi-nationals in the fields of agriculture, research, science & Technology and affect the country's interest."

190. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the atrocities being committed on the tribal women in different parts of Tripura."

191. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the gang rape committed at Union Maidan in Tripura.

192. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:

"but regret that the Address fails to mention about the modernisations mention about of TISCO, Burnpur, in West Bengal."

193. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the modernisation expansion, revitalisation of Cycle Corporation of India and Refractory units of Burn Standard Co. Ltd., etc."

194. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the nationalisation of jute industry."

195. That at the *end* of the Motion, the following *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the extension of suburban services upto Asansole and running of EMU coaches between Barddhaman and Asansol of Eastern Railway."

196. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the need to protect the towns and villages in and around coal mines from gas and fire etc. caused due to slaughter and unscientific mining."

197. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the implementatic

of the rehabilitation package for the people of affected coal mines areas."

198. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about erosion taking place on the left bank of Damodar river in Asansol and Durgapur subdivisions for drawing sands in an unscientific manner.

199. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the need to protect the so-called chronically sick industries and mines from closure and take steps for proper investment in them for modernisation, diversification expansion to make them viable."

SHRI E. BALANANDAN Sir, I move:

200. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the more of the Government for the privatisation of power sector inviting foreign multi-national companies."

201. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to list any steps to harness the hydel capacity of the country for power generation which is a cheaper source of electrical energy."

202. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to indicate that allocation of required funds will be for the rural developmental programmes."

203. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to support the Palestenian Liberation Movement by hobnobbing with the Israel and by crying for a comprehensive and multifaceted relationship."

204. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to indicate the dangerous move of the Government to trying for US-India military cooperation."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments Nos. 205 to 238. S/Shri Chaturanan Mishra, N. E. Balaram, Gurudas Das Gupta, Dr. Z. A. Ahmad. Not here. Amendments not moved.

Amendments Nos. 239 to 270. Shri Ramachandran Pillai.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir I move:

239. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Punjab elections had been marred by very low polling due to the atmosphere of fear generated by the terrorist threats, and due to the manipulations by the Ruling Party and the Union Government which by refusing to announce a political package facilitated by the boycott by the Akalis."

240. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Punjab elections were vitiated by the rigging of the polls in some places by Congress(I)."

241. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the narrow partisan attitude adopted by the Union Government had harmed the cause of national unity by alienating further the mass of Sikhs by heightening the communal gulf in the State."

[Shri Ramachandran Pillai]

242. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Union Government would take immediate steps to implement Rajiv-Longowal Accord."

243. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Ekta Yatra and the subsequent J.K.L.F. march to the Line of Actual Control had deteriorated the situation in the Kashmir Valley with extremists intensifying their activities."

244. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the failure of the Union Government in taking appropriate steps in solving the economic backwardness and regional imbalances has further deteriorated the Assam situation."

245. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the discontent and the struggle for the identity of the tribal people umst be sympathetically considered and maximum regional autonomy should be granted to the contiguous tribal region."

246. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that there is no other way to solve the Ram Janambhoomi-Babri Masjid dispute except by negotiations by both sides, failing which abiding by the court verdict before whom the case is pending."

247. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that Union Government would firmly defend the rights of the minorities and protect them from the ravages of communal riots."

248. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that Union Government would take all steps to end the discrimination practised against the minority in educaton, jobs and social security facilities.'

249. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that new economic policy pursued by the Union Government has far-reaching adverse consequences on the country's economic sovereignty and the people's well-being."

250. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the new industrial policy pursued by the Union Government would adversely affect self-reliance and endanger economic sovereignty."

251. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the new industrial policy was a bonanza for the big industrialists and would work against the small and medium sectors."

252. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the fiscal and budgetary policies of the Government are a nacked attempt to pass of the burden on the common people."

253. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that going in for further IMF loans with the fulfilment of the conditionalities, would lead India into a debt trap and undermine her economic sovereignty."

254. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that increasing budget deficits passes the burden on to the common people through inflation."

255. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the 20 per cent devaluation of the rupee, the indirect taxation and the administered price hike had brought high inflation and stagnation."

256. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the people are suffering due to galloping prices of all essential commodities."

257. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the production dates in several infrastructural areas like electricity, coal, steel, etc. are not satisfactory thereby causing constraints on the growth of the industries."

258. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about failure of Union Government to take steps in solving regional imbalances in the infrastructural facilities."

259. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the new economic policy of the Union Government would adversely affect the progress of Science and Technology in our country."

260. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of the Union Government to implement genuine radical land reforms."

261. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the new policies have opened the doors for multinational penetration in the seeds policy and joint ventures in agroprocessing industry and this would harm the interests of the peasantry and the people in the country.

262. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the army to army cooperation with USA would cause serious adverse repercussions on our foreign policy and endanger national security."

263. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Union Government had entered agreements with U.S. on military collaboration without taking people or parliament into confidence."

264. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the curtailment of powers vested with the Panchayat Raj institutions in Kerala amounts to an attack on the democratic rights of the people."

[Shri Ramachandran Pillai]

265. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the vicious attacks and atrocities on Scheduled Castes, particularly the landless agricultural labour and the steps taken to redress their problems."

266. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the sufferings of the Tribal people who are subjected to the bondage of feudal exploitation by big contractors and landlord and also the rapacious capitalist exploitation and the steps Government intends to take to solve their problems."

267. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the unequal status of women and the double oppression they suffer in contemporary Indian society and the steps Union Government to take to solve this serious problem."

268. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the increasing penetration of communal, casteist and profiteering forces in the education system."

269. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the State's responsibility in providing education for all and to check the rampant privatisation and commercialisation of education."

270. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the necessity to carry forward the struggle to defend secular values and scientific temper in the country."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments Nos. 271 to 302. S/Shri Chaturanan Mishra, N. E. Balaram, Gurudas Das Gupta, Dr Z. A. Ahmad. Not here. Amendments not moved.

Amendments Nos. 303 to 307. Shri Tindivanam G. Venkatraman. Not here. Amendments not moved.

Amendments Nos. 308 to 321. Shri Ananat Ram Jaiswal.

SHRI ANANT RAM JAISWAL (Uttar Pradesh): Sir, I move:

308. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the brutal massacre at Bara in Gaya district of Bihar on February 12, 1992."

309. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the need for containing Government expenditure".

310. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the need to fix a maximum limit of personal income and expenditure."

311. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the starvation deaths and the abject poverty among the handloom weavers of the country."

312. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the ever-increasing prices of cotton and staple yarn."

313. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the starvation deaths in Kalahandi, Orissa."

314. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the sky-rocketing prices of essential goods."

315. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the need to bring all the primary schools at an uniform level."

316. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the scheme proposed to be devised to conserve petroleum."

317. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the need for eradication of corruption."

318. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the acceptance of commission by eminent leaders of the country in the Bofors gun deal."

319. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the acceptance of conditionalities by the present Government under pressure from the World Bank and I.M.F. against national interests."

320. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the backwardness of various regions in the country because of imbalanced development schemes."

321. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the debt trap in which the country finds itself at present."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments Nos. 322 to 335. Shri Yashwant Sinha.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I move:

322. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of Government to hold free and fair elections in Punjab and thus reducing the elections to a mere farce."

323. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that the Government has failed to give a fillip to exports which in fact have recorded a decline and that the increase in the foreign exchange reserves is made up only of loans and other liabilities and does not reflect the strength of the economy."

324. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that expenditure on the plan during the current year has been slashed and development work is likely to suffer."

325. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the adverse impact

[Shri Yashwant Sinha]

on the banking sector of the acceptance of the Narasimham Committee recommendations."

326. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the fact that the prices of essential commodities have gone up by 28 percent during the last six months thus causing untold hardship to the common man."

327. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the fact that under the new economic policy of the Government planning has lot all meaning and the Planning Commission has become redundant."

328. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to effectively tackle soil erosion and land degradation and to come out with a long term land-use plan for the whole country."

329. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to finalise a National Agricultural Policy."

330. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention any plans about creating employment opportunities on a massive scale both for the educated as well as uneducated unemployed."

331. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the growing one-sided military cooperation with the US which is likely to threaten the security of the nation."

332 That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the failure of the Government to honour its own commitment on the floor of Rajya Sabha that establishment of full diplomatic relations with Israel shall have to pend the outcome of the West Asia peace talks."

333. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the manner in which the Government has seriously compromised its position on the NPT during summit meeting of the Security Council and earlier during the visit of US Senator Larry Pressler".

334. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the manner in which the sovereignty of the nation and the dignity of Parliament have been severely compromised as a result of the surrender to IMF/World Bank including discussing budget proposals with them."

335. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails not mention that the Government is not only bartering away its sovereignty but also undermining the constitutional provisions relating to solcalism, individual equality, removal of regional disparities and class distinctions through its new economic policy."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments Nos. 336 to 359. Shri Shabbir Ahmad Salaria, Not here. Amendments not moved.

Amendments Nos. 360 to 369. Shri Shankar Dayal Singh. Not here. Amendments not moved.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, I move.

370. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the failure of the Government to prevent the massacre at Bara in Bihar and the failure of successive Governments in Bihar to protect the lives and property of the weaker sections of society."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments from No. 371 to 399 by Shrimati Sarala Maheshwari. Absent. Not moved.

Amendments from No. 400 to 419 by Prof. Saurin Bhattacharya. Absent. Not moved.

Amendments from No. 420 to 463 by Shri Satya Prakash Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

420. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्वाचन विधि में व्यापक संशोधन लाने की सरकार की मंशा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

421. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

422. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तराखंड की जनता में, उसकी गरीबी और पिछड़ेपन के कारण व्याप्त आक्रोष को समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

423. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों के असंतोष को दूर करने और उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

424. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और इलाहाबाद की मेजा-बारा तहसील में रहने वाले आदिवासियों की दशा सुधारने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

425. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षित और अनपढ़ बेरोजगारी की बेरोजगारी दूर करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

426. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवास समस्या और घर-विहीन व्यक्तियों की समस्या का समाधान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

427. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के पिछड़े क्षेत्रों में विद्यमान स्थितियों में सुधार लाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

428. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

करने और बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक लगाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

429. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों पर हो रहे बर्बर अत्याचारों को रोकने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

430. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की किसी योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

431. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को बिजली की अबाध पूर्ति किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

432. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

433. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मिलावट को रोकने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

434 प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदयिक प्रवृत्ति और तनाव को रोकने के ठोस उपायों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है"।

435. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के अधिकार" को संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

436. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

437 प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

438. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों और भूमिहीन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए किसी भी योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

439 प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसी ऐसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सत्तारूढ दल अपने हितों के लिये दूरदर्शन और आकाशवाणी का दुरुपयोग नहीं करेगा।"

440. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : —

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन

करने वाले व्यक्तियों की हालत में सुधार लाने के लिए किसी समय-बद्ध योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

441. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़, अतिवृष्टि और सूखे के कारण प्रति-वर्ष होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किन्हीं ठोस व समय-बद्ध योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

442. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समस्या का समाधान ढूंढने के लिए शांति बहाल करने और आतंकवाद को रोकने हेतु किन्हीं ठोस और समय-बद्ध योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

443. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में बमरौली हवाई अड्डे की स्थिति में सुधार करने और उसे आधुनिक बनाने की कोई योजना नहीं है।"

444. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इलाहाबाद और भटनी के बीच, वर्तमान मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

445. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पेयजल के अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी के अभाव की समस्या को हल करने की आवश्यकता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

446. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण जनता द्वारा रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

447. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरों में गन्दी बस्तियों की निरन्तर वृद्धि पर रोक लगाने की आवश्यकता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

448. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील, भद्दे और कामुक पोस्टरों के लगाये जाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।"

449. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी काम-काज में अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर, जो एक विदेशी भाषा है और उपनिवेशवाद का प्रतीक है, रोक लगाये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

450. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभा ण में चीन द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जे में लिए गये भारतीय भूभाग की वापसी के लिए किसी योजना अथवा 1962 के लोक सभा संकल्प के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

451. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए किसी

[सत्य प्रकाश मालवीय]

समय-बद्ध योजना के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

452. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुग्ण उद्योगों में सुधार लाने सम्बन्धी किसी योजना के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

453. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की दशा में सुधारों लाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

454. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों से अधिगृहीत की गई भूमि के लिए उन्हें उपयुक्त मुआवजे का भुगतान करने हेतु किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

455. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार अथवा आम जनता की चिन्ता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

456. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी व्यय में अपव्यय को रोकने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

457. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम आदमी को कम लागत पर त्वरित न्याय दिलाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

458. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आय और व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नही किया गया है।"

459. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राम-जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

460. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारी संकल्प के अभाव तथा उसकी अक्षमता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

461. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋणों के निरन्तर बढ़ते हुए भार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

462. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन तथा विदेशों में भारतीयों द्वारा जमा किए गए धन का पता लगाने और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

463. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments from No. 464 to 473 by Shri Md. Salim. Absent. Not moved.

Amendments from No. 474 to 480 by Shri Debabrata Biswas. Absent. Not moved.

Amendments from No. 481 to 495 by Shri Ramdas Agarwal. Absent. Not moved.

Amendments from No. 496 to 525 by Shri Ram Awadhesh Singh. Absent. Not moved.

Amendments from No. 526 to 530 by Shri Ish Dutt Yadav.

SHRI ISH DUTT YADAV (Uttar Pradesh): Sir, I move:

526. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the intention of the Government to implement the recommendations of the Mandal Commission for the uplift of Backward Classes."

527. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the deteriorating Law and Order siutation and increasing terrorism in the State of Uttar Pradesh."

528. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention any programme to speedily solve the problem of unemployment and remove the growing dissatisfaction among the unemployed youth."

529. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the strong steps to be taken by the Government to check and control the increasing prices of essential commodities."

530. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the clear intention of the Government to remove the regional imbalances in the country."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments from No. 531 to 538 by Shri V. Gopalsamy.

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, I move:

531. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the recent revelation regarding payment of Commission in Bofors Gun deal, which appeared in DYDEN NHYTER, a Swedish Newspaper and steps to be taken to expose the real culprits in the Gun deal."

532. That at the *end* of the Motoin, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the total surrender of India's Economic sovereignty at the feet of World Bank and IMF thereby opening the doors in India for the encroachment of Multinationals."

533. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mentjon about the implementation of the recommendations of the Mandal Commission to establish social Justice.

534. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Christians belonging to the SC and ST communities will be given the same status and rights and privileges enjoyed by the SC and ST persons following Hindu religion."

[Shri V. Gopalsamy]

535. That at the end of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the significance of sanctioning and implementing Sethusamudram Canal Project."

536. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that with a view to protect the unity and integrity of the country Nehru's assurance to Non-Hindi speaking people about the continuation of English will be incorporated in the Constitution."

537. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the deletion of Article 356 of the Constitution to uphold the concept of federalism."

538. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about Government's failure to safeguard the rights of citizens from the indiscriminate use of TADA for offences falling under the general and penal laws of the country and to direct the State Government not to use TADA in a vindictive way to harass their political adversaries and peoples' representatives and the need to review immediately ways like TADA."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendments from No. 539 to 546 by Dr. Nagen Saikia. Absent. Not moved.

Amendments from No. 547 to 556 by Shri Pasumpon Tha. Kiruttinan.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN (Tamil Nadu): Sir, I move:

547. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about Government's failure to safeguard the rights of Citizens from the indiscriminate use of TADA for offences falling under the general and Penal laws of the country and direct the State Governments not to use TADA in a vindictive way to harass their political adversaries and people's representatives and the need to review immediately laws like TADA."

548. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to take timely steps to solve the Cauvery water dispute."

549. That of the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about Government's intention to implement the recommendations of Mandal Commission securing thereby the rights of the backward and most backward classes of the country and honouring its commitment in that regard."

550. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the devaluation of the Indian Rupee which has started causing economic imbalances throughout the country and spiralling of prices which terribly affect the common man."

551. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the growing unemployment problem of the country."

552. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the deviation of the Government from the non-alignment policy."

553. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the hike in prices of essential commodities causing untold hardships to the people of this country."

554. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the restructuring of the Constitution of India on federal basis and giving of more autonomy to the States."

555. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the significance of sanctioning and implementing Sethu Samudram Canal Project."

556. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the total surrender of India's economic sovereignty to the World Bank and IMF thereby opening the doors in India for the economic domination and encroachment by the multi-nationals."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Amendment No. 557 by Shri Mentay Padmanabham. Absent. Not moved.

Amendments from No. 558 to 567 by Shri Bhupinder Singh Mann. Absent. Not moved.

Now the amendments are moved. Whatever amendments are moved...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I was although present in the House but when you called my name I went to take a glass of water. I may be allowed to move all my amendments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is your request? I am not following

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I may be allowed to move all my amendments.

SHRI KAMAL MORARKA: He had gone to the Lobby for two minutes and he missed it,

SOME HON. MEMBERS: It cannot be done.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Your name was called but you were not present. Anybody wants to say anything on this?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): It is not possible.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Nothing is going to be lost.

SHRI V. NARAYANASAMY: No, Sir. We have to go by the rules.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, you call an amendment. If the hon. Member is present, he can move the amendment. If he is not present, you rule that the amendment is not moved. You cannot go back on time. (*Interruptions*).

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu): Sir, heavens will not fall. (*Interruptions*).

SHRI P. CHIDAMBARAM: Suppose tomorrow another Member comes and says, "I did not know that the amendments would be put at 3.30 p.m. I came at 5 O'clock. And I have come today, you allow him to move the amendments tomorrow?

SOME HON. MEMBERS: No. Not tomorrow.

SHRI MURASOLI MARAN: Before you close the subject, the hon. Member is coming. So, he may be allowed. (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, this will be opening the Pandora's box.

[Shri V. Narayanasamy:]

Then two or three more Members will come and they will also insist on moving their amendments. (*Interruptions*).

SHRI R. K. DHAWAN: If somebody gives a notice that he wants to move a fresh amendment now, will you allow him?

SHRI V. NARAYANASAMY: Why should we violate the rules? (*Interruptions*). Sir, what is your ruling?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I am giving my ruling.

SHRI ASHIS SEN: It was not wilful absence. It was need-based absence. Need-based absence should be given consideration. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It does appear that the subject of moving amendments was not over when the hon. Member requested the Chair. I think he should have an opportunity to move the amendments. (*Interruptions*).

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Sir, you will also say that it will not be a precedent. Otherwise, it will open the Pandora's box.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The position appears to be, as I got ascertained, that it is in the discretion of the Chair if an explanation is given properly and the subject is not over. It does appear that the subject is not over.

SHRI V. NARAYANASAMY: It will be a precedent for others.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is not a precedent.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): He can move all other BJP Members' amendments also because he is now present.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Out of a group, anybody can move.

SHRI H. R. BHARDWAJ: If there is an hon. Member who has a sort of personal amendment and if he is not present for a short while, it is all right. But nobody is taking them seriously. None of the BJP Members is there. Will he move all the amendments for them? This is a bad precedent.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the amendment to be moved by him should stand in his name. The names of other Members should not be called.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. S. P. Gautam, amendment Nos. 1 to 6, 62 to 74, 112 to 124 and 125 to 130 stand in your name as well as in the names of other Members. But you can move them because you are present. And I have permitted you as a special case. You can move all these amendments.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir I move:

1. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

   "but regret that the Address does not mention about any effective action plan to solve the growing problem of unemployment amongst the youth of the country."

2. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

   "but regret that the Address does not mention about the executive of an effective action plan on priority basis to remove the increasing imbalance in the development of different regions in the country."

3. That at the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

   "but regret that the Address does not mention about any effective and far-reaching measures proposed to

be taken to check the continuously rising trend in the prices or essential commodities and other consumer goods of use to the common man."

4. That at the **end** of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any integrated plan to check the growing Naxalite menace in several parts of the country, particularly in the States of Andhra Pradesh, Maharashtra, Bihar and Orissa."

5. That at the **end** of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to indicate any definite time frame to introduce legislation for comprehensive and consolidated election reforms."

6. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to indicate any policy on Jammu & Kashmir and to put down the militancy and secessionism there."

62. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about Government's plan to reduce the litigation expenses by initiating suitable action for setting up of benches of High Courts at different places in the States and likewise establishing benches of the apex Court of the country zone-wise."

63. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the steps Government have in mind to improve the Public Distribution System."

64. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the measures Government proposes to take to rejuvenate the fertilizer industry, especially when some units are facing closure."

65. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the steps to be taken for ending the burden of foreign debts."

66. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any plan to provide relief to the poor consumers of the country by bringing down prices of essential commodities."

67. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address as to when the existing education system will be changed to make it an employment-oriented one."

68. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the address does not mention of a time bound programme for making special arrangements for the promotion of education in areas inhabited by people belonging to the backward classes and poorer sections of the society so that they come up to the standards of the people of other prosperous sections of the society in the country."

69. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no indication in the Address that Centre-State relations would be reviewed with a view to give more autonomy to the States."

[Shri Sangh Priya Gautem]

70. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any programme for the prevention of child labour in the country."

71. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken in respect of public sector enterprises which are incurring losses, either to close them or make them profitable units once again."

72. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the steps to be taken to improve the lot of landless agricultural labourers."

73. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the steps to be taken to tone up the Administrative machinery, achieve utmost economy and curtail wasteful expenditure in the administration."

74. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention about setting up of a University or an Institution of national importance in the name of Dr. B. R. Ambedkar."

112. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not spell out concrete proposals for village upliftment."

113. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any plan to check the imigration of rural people to urban areas in the absence of proper living conditions and also due to their poor economic conditions."

114. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not give any assurance to the landless agricultural labourers and Adivasix that they would no longer be required ot migrate to other States in search of livelihood."

115. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address as to how Government intends to put an end to the ongoing caste clashes in rural areas."

116. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about schemes to link the villages and the towns with nearly national highways."

117. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address for encouraging the establishment of more cottage industries in rural areas."

118. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address for improving the supply of drinking water in rural areas."

119. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any scheme to apprise the poor and ordinary farmers, about the last researches in the field of agricuture."

120. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about Government's desire to bring forward crop insurance scheme for farmers."

121. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not spell out Government's intention to bring an end to large scale bungling in the public distribution system."

122. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about starvation deaths in some parts of the country and Government's resolve to prevent these most unfortunate incidents, particularly in view of its claim of all round progress in the country."

123. That at the end of the Motion, the the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about Government's failure to build up public opinion against activities of secessionists and militants in some parts of the country."

124. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of Government to inculcate a sense of oneness amongst people of the country."

125. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address to improve Centre-State relations with a view to give more autonomy to the States."

126. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address as to what action Government proposes to tackle the situation arising out of the losses being incurred year after year by some public sector undertakings."

127. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be initiated to check the high administrative expenditure."

128. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in in the Address about any plan to improve the public transport system in the Union territory of Delhi."

129. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about Government's intention to initiate electoral reforms by suitably amending the Representation of the People Act."

130. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about Government's intention to identify chronic cyclone prone areas in the country with a view to sanction special assistance to the affected States."

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, the Motion, along with the amendments moved, is before the House for consideration. And the speaker is Shri M. S. Gurupadaswamy.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, there is a very old popular Spanish story. Once an illiterate Spanish farmer wanted to go to a destination and he went to the railway station to catch the train for that destination. He saw a train standing there Thinking that train would take him to that destination, he

[Shri M. S. Gurupadaswamy]

entered the train. The train started and it obtained accelerated speed as it went on. But the train was really going in the opposite direction in high speed. The farmer thought it is wonderful that the train is running very fast and will be reaching the destination. After some time, he landed himself in the opposite destination. Shri Narasimha Rao's Government is creating an illusion in the mind of many people that he is taking the nation to a forward destination; he is taking the economy to a forward destination. On the contrary, he is taking the nation backwards and he is reversing the gear, perhaps, and he is creating a false feeling in the mind of many people that the nation will be safe with him since the piloting or steering of the nation is in his hands and people should trust him. That is the situation today. The Government of India is reversing the whole process of socio-economic transformation and he is setting the clock back, if I may say so. The mover of the Resolution pleaded that the Opposition should support him and should support the President's address. I could have supported him. I could have supported the President's address and I can still support the President's address if it can be done ... if the President's Address is recast, recast in such a manner to defend, protect and save our national honour, national sovereignty and economic independence. I do not say that the Government is suffering from mala fide intention. No; the Government is in the predicament of the Spanish farmer, the story just now I narrated. They are unconsciously ignorant, they are giving up all the legacies, the values and the achievements of the past. Though those are not very great, still they are worth preserving. The economic policy of this country which is being announced, the trade policy, the exchange policy, the fiscal policy, which have been announced, is a joint exercise of the Government of India, the World Bank and the International Monetary Fund. From that point of view I say it is hybrid. There is no use in saying that these policies have been framed by the Government itself. If you go through all the conditionalities and prescriptions. 25 prescriptions and directions given by the World Bank,—which I don't want to narrate—they have been done before by my colleagues—,the House will realise that the Government of India has become a supplicant, a puppet, unfortunately in the hands of international agencies and the multinationals. We know what happened to countries which have taken such help in the past. The expectations, the dreams and the hopes created at the time of taking such assistance and help from these institutions and the multinationals landed those countries, particularly Latin American countries, in great trouble. We have to draw a lesson from them.

Sir, I expected the Address to be lucid, clear and far-sighted, but it has turned out to be a non-descript document, a lack-lustre document. A narration of events no doubt. It is a catalogue of various things, just a catalgoue. The President's Address has got to be luminous, transparent and inspiring. The President's address is a unique document. Once in every year the President addresses the sovereign Parliament. It is a unique occasion and that occasion has got to be utilised by the President or by this Government to tell the country the state of affairs—the crisis, if there is any. I searched the address to find out whether there is any reference to the crisis in the address; whether the address has identified the crisis which we are facing. What is the crisis? What is the nature of the crisis? What is the dimension of the crisis? What are the consequences flowing out of this crisis? What are the remedies, I tried to find out these things and the answers. I was totally disappointed. Nothing is there except a cataloque of events—a dull and drab narration at the most.

What is the crisis? Let me identify in my own humble way. What is the crisis we are facing? Without understanding this crisis and the genesis of this crisis, we cannot find effective remedies. And what is this crisis? The crisis is multi-dimensional, multi-faceted. Can I call it a political crisis? Yes, it

is a political crisis. Shall I say it is an economic crisis? Yes, it is an economic crisis. Shall I say it is a moral crisis? Yes, it is a moral crisis. Shall I say it is a crisis of the administration? Yes. Is it a crisis of the Government? Yes. Is it a crisis of political parties? Yes. And is it a crisis of the whole society or the nation? Yes. It is a total crisis and you cannot deal with this crisis with the 25 commandments issued by the World Bank. These 25 commandments will not lead you to paradise; it will lead you to hell. That is what I want to submit.

Sir, there is growing polarisation in our society—polarisation based on caste, based on religion, based on language, based on region, based on sects, based on States. People are talking of the nation less and less and talking more and more of region, language, religion, caste, creed and so on. This is a social crisis. How do you deal with this crisis? I expected the President's address to, at least, focus on the crisis—the nature of the crisis. It was not done. It was missing. The mover of the Resolution referred to our boycott of the President's address. It was not an easy decision to take. We have run Government in the past—some of us here. It pained us to take such a decision. Why did we take that decision to boycott the President's address? It is a solemn occasion. Why did we do it? What was the compulsion? What was the imperative? When the whole nation's honour, self-respect and sovereignty were being compromised, when there was a sell-out of the nation, our honour to international agencies, when Parliament is not taken into confidence, the minimum that we expect as Members of Parliament is that we should be taken into confidence. We have the right to information, to assist important decisions. We may not decide, but we must have the opportunity of being consulted before a decision is taken by the Government. Such an opportunity was denied to us. I thought Mr. Narasimha Rao being an experienced person, good in handling parliamentary affairs, would consult all of us and would wait or call a special session. He never did it. Today Parliament has been reduced to a rubber stamp. That is why, we thought when the sovereignty of Parliament, the paramountcy of Parliament, the right of Parliament, is being bypassed and abridged—may be deliberately or may not be deliberately—we should not compromise on this. Sir, there is a biblical saying: If salt loses its savour, where is it to be salted? If the sovereignty, the dignity and the right of Parliament is denied, denigrated, where do you turn to? That is the question which was before our mind. And that is the reason for the boycott. With great pain and sorrow we did that. We have got the greatest respect for Rashtrapatiji. I have the highest regard for my friend, Mr. Narasimha Rao. But we all owe a duty to the nation. And our nation is more important than all of us. When a unique institution like Parliament is being treated with scant courtesy, we thought we should register our protest. When the Ministry was wittingly or unwittingly, making our country a hand-maid of international agencies, we thought we should protest. That is what we have done. Sir, the President has, of course, narrated many events. I start with Punjab?. What is happening in Punjab? Elections were held there. We are not against elections. But we thought, when elections were held all the political parties would participate. That was our expectation. Mainly those parties who command the majority support in the State would participate; otherwise, the election has no meaning. It would be a farce of an election. That is what has happened. A sort of election has been held. In what way has it been held? There were stories, stories, and stories circulated everyday and the voter was perplexed, confused and....

4-00 P M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Gurupadaswamy, one minute. There is one matter which I must record. There were two requests, one by Prof. Saurin Bhattacharya and the second by Mr. Salim, with regard to amendments 400 to 419 and amendments 464 to

[Shri Bhaskar Annaji Masodkar]

473 to be permitted to be moved. I have checked up; it cannot be done because the discussion has already started. So my ruling is, both these requests cannot be granted. Mr. Gurupadaswamy, please go on. Sir, the voter in Punjab was pressed on one side by the gun of the militants and on the other by the gun of the militants and on the other by the gun of the security forces. And he had to vote. What was the turnout? You call it 30 per cent. It was 25 per cent or 21 per cent or near about. I am not criticising. But this is not the way of holding elections. We had elections in Kashmir also. Let us learn a lesson. You may win. I am not quarrelling on that point. After all, in a democratic country you may win or we may win. I am not quarrelling. But I am pointing out the mistake, the blunder that you are committing, and the short-sightedness. In Punjab what I see is a political travesty. Perhaps by holding elections you have created a new poignant situation, a vicious situation. People in Punjab will have a feeling in their hearts that they could not vote due to various compulsions, whatever they are. And even now the militancy and violence is continuing. It is unfortunate. I am not blaming anybody. Elections have not brought down violence. Extraordinary powers under the law are being used. TADA and others are being used even today. I thought when the elections were held, there would be an end to these extraordinary powers under the law, law and order would be restored, peace would be restored. It is not there. Punjab has got to be approached politically. Even now I say, use the present Government by all means — I do not know whether the present Government enjoys the confidence of those people, of the people of Punjab; whether it has got credibility, legitimacy, I do not know; but if you can use it, then use it. But let there be a solution to Punjab. The issues are clear. Rajiv-Longowal Accord is there. Make it as a basis and invite the Government of Haryana as well to a round-table conference. Sort out these problems. Mr. Narasimha Rao is credited to have said the time is running out and, therefore, they had to go to the World Bank. May I say the same thing in respect of Punjab? The time is running out, for God's sake please find a solution to Punjab and consult the leaders of the Opposition. All of us here have got one mind, that the problem of Punjab has got to be solved amicably through negotiations and not through the bullet. This has to be done. There is nothing in the Address. It does not throw any light at all on this problem. It is a crucial problem. Likewise, Kashmir; what do you find in the Address, except a bald statement? Pakistan is trying to internationalise the issue-trying to put the Kashmir issue on the international agenda, doing everything to destabilise the Kashmir valley and the people of Kashmir are alienated. The administration is inefficient and corrupt. There is no development in Kashmir. For the last so many years you have seen how the Governments in Kashmir have run. To my information, there were ten Ministries in the past. All these ten Ministries, I say without any exception, did not command the full confidence of the people in Kashmir because they were all puppet Government working at the behest of the Centre. In future, the Government of India has to make up its mind to change its approach, strategy in Kashmir. Security forces alone cannot solve the problems of militancy or cross-border infiltration. We have to talk to Pakistan in the language they understand. We have been talking about the Shimla Agreement Let Mr. Narasimha Rao take initiative and invite his counterpart for negotiation on the basis of the Shimla Agreement. Let there be a settlement of Kashmir by negotiation. Negotiation should not be held out of fear and we should not fear negotiation. I plead with the Government that this running sore of Kashmir should be effectively dealt with, should be solved quickly and Pakistan has got to be told that while we want to be good neighbour friendly to Pakistan, we do not tolerate the interference of Pakistan or the interference by the militants supported by Pakistan in Kashmir affairs. Negotiation is the only way. We should have it. You

tell Pakistan that the resolutions of the United Nations is a bygone resolution. So many developments have taken place and so many events have taken place since then. Even the resolution on Israel, Zionism, has been changed by the United Nations. Therefore, the resolution passed by the United Nations long back under different circumstances cannot be considered as sacred and they should know it. We should give a warning even to the friendly countries in the West that we do not tolerate interference in Kashmir affairs by anybody. This message has got to go. Our diplomacy has got to be very effective and strengthened. Then, the question of Assam.

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): I would like to know one thing. The hon. Member is the leader of the Janata Dal. So, Whatever comes from him is of vital importance. The hon. Member has said that the hon. Prime Minister of India should not shy away from negotiations on the question of Kashmir with his counterpart in Pakistan. I would like the hon. Member to clarify. Does he mean that he should hold negotiations to tell the Pakistan Prime Minister that so far as the status of Kashmir is concerned it is not negotiable and interference will not be tolerated? Or does he mean to suggest that these negotiations will cover the question of the future status of Kashmir. This is very important. (*Interruptions*). That is not a matter of debate. He is a leader of Janata Dal, a very important national party, and he must clarify their stand. (*Interruptions*)

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I value his intervention, Sir. I said during my speech that Pakistan should not interfere in Kashmir. I also said that the Resolution passed by the United Nations long back is a bygone Resolution; it has lost its meaning now in the new situation. I also said that the Simla Agreement should be the basis on which talks should be conducted. I think I am very clear on that. So, it is not a question of doubting my candour. On this I am very clear. When I am saying that India should not be bartered away, should not be surrendered, it includes Kashmir also. This is the tenor of my speech.

Sir, the President also referred to Assam. Assam is another area where militancy, violence and terrorism are indulged in on a large scale by ULFA. The entire north-eastern area still is vulnerable. I would like the Government to solve this problem effectively. One reason why the ULFA activities increased was that that they were able to tell the people that Assam was being ill-treated or not treated well at the hands of the Centre. I was dealing with Assam, let me tell you. They had a feeling wrongly that they received a step-motherly treatment at the hands of the Central Government. When I was in Government, Sir, I did my utmost to give a lot of assistance because I know that this psychology was built up, rightly or wrongly, over a period of years. This psychology has got to be removed from the minds of the Assamese. a psychology which encouraged a feeling that without more autonomy, without opposition to the Government of India, justice will not be done to Assam. That feeling is created. During our time, Sir, we did so much; even earlier, when Rajiv Gandhi was the Prime Minister, there was an Accord. And we followed it up. And I gave nearly Rs. 8,000 crores worth of projects to Assam thinking that it would convince them that the Central Government is always helpful to them, more helpful to them. And I also assured them when the delegations came to me that there will be employment of Assamese in all the oil sectors provided they fulfil technical qualifications at par with others, and that they would be preferred. All this was done. Even today, I think, they are continuing with it. But the psychology of this kind has got to be removed.

Sir, now there has been a talk of negotiation with the ULFA activists. I am told there are two wings now. One wing does not want to co-operate; another wing wants to co-operate, they want to

[Shri M. S. Gurupadaswamy]

negotiate. But the progress of negotiations is very slow. I thought the President's Address would cast some light on this as to what progress has been made so far in Assam on this issue. Besides the ULFA, the Bodos are there; others are also there. There has got to be a package; if not a package, at least their grievances, their demands have got to be met. This is the problem. So, in the President's Address there is nothing to suggest how we are tackling the problem.

Sir, I said, the crisis is multi-dimensional. In that I stated that each region, each State is developing a sub-regional consciousness or sub-national consciousness. They are making a lot of claims and demands over the Centre. It is a very live question. It has been there for long, built up for decades. Centre-State relations is a live issue, an important issue. Even the problem of Assam and Punjab can be solved by dealing with this issue of Centre-State relations. Sarkaria Commission Report was submitted long back. I am told that some sub-committees have been constituted to study various aspects of the Sarkaria Commission Report. But solutions are wanted, remedies are wanted. There has got to be response to the States' demands. Today, there is no alternative, no escape, let me tell you, than to recast our federalism. I am not saying that there should be a radical departure from the Constitution which we have. But with minor adjustments, with little changes, minimum amendments in the Constitution itself, there can be a harmonious relationship established between the Centre and the States. Otherwise, this conflict will continue. The issue of unity of the country itself is involved. The fabric of the society will be destroyed. Therefore, I say that priority has got to be given to recast Centre-State relations on a rational, logical basis. And more decentralisation is necessary. In this context, may I say that decentralisation of Power has got to be taken to the grass-roots? It should not stop at State capitals. Village panchayats, local panchayats have got to be established. There has got to be self-reliant participatory democracy, grass-root participatory democracy emerging, and that will be the bullwark for keeping society in tact. But that has not been done. Priority has not been given during all these four decades. I am sorry to say that the country has been brought to this mess because of misdirection of resources on the one side and misplacement of priorities on the other. These are the two things. It is high time when you have got to look into these things. But that is not being done. Shri Manmohan Singh says our God is World Bank and therefore we go to the World Bank...

SHRI V. NARAYANASAMY: Don't put words into his mouth.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): It is a misunderstanding.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Let us not think that the World Bank and the international agencies or the multinationals will solve our problems. But you go to the World Bank. We talk of structural reforms, macro economic stabilisation. I am also a student of economics. I want to understand this. What is the structural reform that one can think of unless there is a structural reform at the grass-root level? Begin with the beginning. Reform cannot come from above. Reform cannot come merely through monetary approach or fiscal approach. There are people living in the villages. Poverty is there; unemployment is there; illiteracy is there; population growth is there. As I said, for the last 40 years, the country has been suffering from misplaced priorities. We could have turned the whole society, the whole nation into a modern vibrant strong nation if we had tackled population problem, education problem, unemployment problem and poverty problem. These are the four overriding problems. But never it was done. Even today it is not being done. And we talk of economic stabilisation, structural transformation. Structural transformation should begin in the rural areas, from the grass-root level. But you are confining all your philosophy to the portals of the

Reserve Bank and a few other banks and International Monetary Fund and the World Bank. They cannot bring about any metamorphosis in our system.

Sir, one of the biggest blunders that this Government has committed is devaluation. We have seen devaluation of the past, the 1966 devaluation.....

AN HON. MEMBER: One hour taken.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I think I have taken less than that. Anyway, it is for the Chair. May I continue?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I think you will have to continue tommorrow because I am told special mentions were already announced to be taken up at 4.30. So we take up special mentions.

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shri Gurudas Das Gupta, not here. Shrimati Bijoya Chakravarty not here. Shri Kamal Morarka.

Need to increase oil production in the country

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir through you, I wish to draw the attention of the Government to the declining oil production in the country.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Oil production?

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, in the last seven-eight months, we have heard about the macro-economic adjustments the Government wants to make. In the Budget also, which has come recently, there has been a lot of focus on the balance of payments position and the foreign exchange reserves. The figures for the last four years show that on one item alone, namely, oil, crude oil, as well as other petroleum products, we have been spending a lot of foreign exchange. The oil bills has gone up from Rs. 4,000 crores in 1988-89, to Rs. 6,000 crores, Rs. 11,000 crores, and now Rs. 12,000 crores, in 1991-92. From 1988-89 to 1991-92, it has gone up three times. it is now Rs. 12,000 crores. The trade Balance, the adverse trade balance, on the other hand, has been Rs. 8,000 crores. It has now reached—Rs. 10,000 crores, which means that whereas, over the last four years, excluding oil, there used to be a trade imbalance of Rs. 4,000 crores, today, excluding oil, there is no trade imbalance. Our entire trade imbalance today is due to oil.

Sir, oil is one item which can make or mar the future of the country. This is so, whichever Finance Ministers may come and whatever structural adjustments they may make. When the Budget comes, the immediate discussion is on some tax. Somebody gets some tax relief. Some excise duties are increased. Some customs duties are increased. On the basis of that, newspapers write that it is a good Budget or a bad Budget.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I would request hon. Members to remain silent.

SHRI KAMAL MORARKA: In the long run, the only thing that can bring stability to the country's economy is self-sufficiency in the energy sector, apart from the food sector. In the case of food, in the seventies, because of the Green Revoloution, fortunately, because of the policies of late Mrs. Gandhi, we are in a position today where we do not have to import foodgrains. I do not want to digress on the subject. I hope this policy will continue. I hope this policy will be continued, even if it means continuation of fertiliser subsidy, etc. But on the energy sector, I am very clear that the Government must take it up on a war-footing.

Already three rounds of bids have been completed, to involve international companies in oil drilling and exploration. Of